भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

सकारात्मक साप्ताहिक हिन्दी अखबार

जागरूक जनता

10 दिसम्बर- 16 दिसम्बर 2025

jagrukjanta.net

मार्गशीर्ष, पक्ष - कृष्ण, तिथि - षष्ठी, संवत 2082 पृष्ठ : 8+2 जयपुर, बुधवार वर्ष-11, अंक-41, मूल्य ₹ 5/- वार्षिक मूल्य : ₹ 250/-

प्रवासी महाकुंभ आज से

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुटेगी उद्योग जगत की हस्तियां

1 लाख करोड़ निवेश और सांस्कृतिक रंगों का संगम

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान 10 दिसंबर को जेईसीसी में पहली बार 'प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025' आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का लक्ष्य दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में होने वाला है और राज्य सरकार इसे वार्षिक उत्सव के रूप में देखने की तैयारी में है।

राज्यपाल कटारिया और केंद्रीय मंत्री गोयल भी आएंगे

उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य उद्बोधन होगा। मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। समारोह की शुरुआत 'प्रगति पथ' प्रदर्शनी से होगी, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल की विकास यात्राओं को दिखाएगी।

सेक्टोरल सेशंस, 7 प्रमुख क्षेत्रों में चर्चा

दोपहर के बाद सात सेक्टोरल सत्र होंगे–रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन और खनन। कार्यक्रम का आधिकारिक शेड्यूल उद्घाटन (11:00-13:00), लंच (13:00-14:00) और समानांतर सत्र (14:15-18:30) के बाद सांस्कृतिक संध्या (19:00) और डिनर (19:45) का प्रावधान दिखाता है।

उद्योग जगत की कई दिग्गज हस्तियां रहेंगी मौजूद

कार्यक्रम में शामिल होने वाली उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां में अनिल अग्रवाल (वेदांता), अजय पीरामल (पीरामल ग्रुप) और प्रवीर सिन्हा (सीईओ व एमडी, टाटा पावर) का नाम सबसे ऊपर है। ये सभी राजस्थान में निवेश, बदलते औद्योगिक माहौल और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों पर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों (MoUs) की ग्राउंडब्रेकिंग रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। राज्य सरकार के अनुसार, इससे Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 के बाद धरातल पर उतर चुकी परियोजनाओं का कुल मूल्य 8 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसी मौके पर "Commitment in Action" कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी प्रस्तावित है।

ओपन हाउस/राउंडटेबल और सम्मान

दिन भर में प्रवासी राजस्थानियों के साथ डायलॉग/ओपन हाउस सत्र रखा गया है, जहां निवेश के अवसरों और सहयोग पर खुली चर्चा होगी। साथ ही 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान' देकर विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य सचिव के संबोधन से होगा समापन

कार्यक्रम का समापन राजस्थान के मुख्य सचिव वी। श्रीनिवास के संबोधन से होगा। समापन के वक्त शाम को सांस्कृतिक रंगों की छटा दिखेगी। घूमर और कालबेलिया जैसे पारंपरिक नृत्यों और फ्यूजन परफॉर्मेंस के जरिए राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, कार्यर् म के लिए हजारों प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और राज्य सरकार इसे वैश्विक जुड़ाव के बड़े मंच के रूप में पेश कर रही है।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज

ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- »मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- »सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- »असाध्य घाव/शुगर के घाव
- »कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- »अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- »डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133

डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.

नेशनल हायपरबैरिक रिसर्च सेन्टर
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर

Dept. of Hyperbaric Medicine
Fortis Escorts Hospital
JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur

E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

कहीं आप गलत तेल के शिकार तो नहीं हो रहे है ?

देसी दिल के लिये, दादी वाला देसी तेल...

Kabira® Healthy Growth Yellow Mustard Oil

Natural Immunity Booster | FORTIFIED WITH VITAMIN A & D2 | 100% VEG. | COLD PRESSED | KOSHER | India's Most Trusted Brand | Approved by : WHO GMP | one of the OLDEST OIL known to HUMAN

स्वदेशी पीली सरसों का तेल है, प्राचीन, पौष्टिक एवं परखा।

- प्राचीन शीतल विधी घाणी से निर्मित।
- निर्माण विधी उच्च ताप रहित ।
- निर्माण में कोई रासायनिक प्रयोग नहीं।
- केन्सर को रोकने में लाभदायक ।*
- मधुमेह को नियंत्रित करने में लाभदायक ।
- एसीडीटी एवं गेस्टिक रोगों में मददगार ।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने मे लाभदायक ।
- केवल देसी सरसों द्वारा निर्मित ।
- मोटापा घटाने में लाभदायक ।
- बालों के लिए एक उत्तम तेल ।
- ओमेगा 3 एवं ओमेगा 6 से भरपूर ।
- तीखी गंध रहित होने के कारण सभी व्यंजनों में उपयोगी ।
- अनेक औषधीय गुणों से भरपूर ।
- सभी तेलों के मुकाबले सबसे कम सेच्युरेटेड फेट्स ।*
- छः हजार वर्षों से मानव के लिए उपयोगी ।

Kabira Cold Pressed Oils are Also Available in :
Kachchi Ghani Mustard Oil (Pungent Smell)
Kachchi Ghani Groundnut Oil | Kachchi Ghani Sesame (Til) Oil

स्वस्थ जीवन के लिए कोनसा तेल उपयोग करें ?

तेल आप उपयोग करें	तेल आप उपयोग ना करें
कबीरा पीली सरसों का तेल	कबीरा रिफाईण्ड पामोलीन तेल
कबीरा कच्ची घानी सरसों का तेल	कबीरा रिफाईण्ड राईस ब्रान तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल	कबीरा ब्लेन्डेड एवं कनोला तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड तिल्ली का तेल	कबीरा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड बादाम तेल	कबीरा रिफाईण्ड सूरजमूखी तेल
	कबीरा रिफाईण्ड मूंगफली तेल

कबीरा पीली सरसों तेल को फेक्ट्री मूल्य में लेने के लिए इस विज्ञापन एवं अपनी डिटेल्स को 90017-99117 पर व्हाट्सप करें और फ्री में लाइफ मेम्बर बनें एवं पाएं 590 रू. की चांदी की फ्रेम एवं केनवास बेग बिलकुल Free
ONLY FOR NEW MEMBER, LIMITED TIME OFFER

समस्त व्रत एवं उपवास में उपयोगी	केवल कबीरा कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल
सर्दियों में उपयोगी	कबीरा कोल्ड प्रेस्ड तिल्ली का तेल
हर मौसम में उपयोगी	कबीरा पीली सरसों एवं कच्ची घानी सरसों तेल
दिपावली, दिपक प्रज्वलन के लिए	कबीरा तिल्ली एवं कच्ची घानी सरसों तेल

-: Awards & Achievements :-

To Open Kabira Hand Made Exclusive Store or Other Trade Inquiries Please Contact :
MANISHANKAR OILS PVT LTD
+91 98290 50738
www.manishankaroils.in
ALSO DEALS IN KISAN, PEEURA, TILAK, HANDMADE, MURARKA, BANSI, KABIRA COLD PRESSED (EDIBLE OIL, SPICES & TEA)

For Arward Details : Contact 98290-50738

★ In Reference to : Asian Journal of Dairy and Food Research (2019)

#GOVERNMENT OF INDIA'S NATIONAL AWARDED #GOVERNMENT OF RAJASTHAN'S UDYOG RATAN AWARDED

NOTHING (R)

Phone (3a) Lite

Starting from ₹19,999*

*Inclusive of ₹1,000 instant bank discount

Glass finish
50 MP Main camera
Glyph light

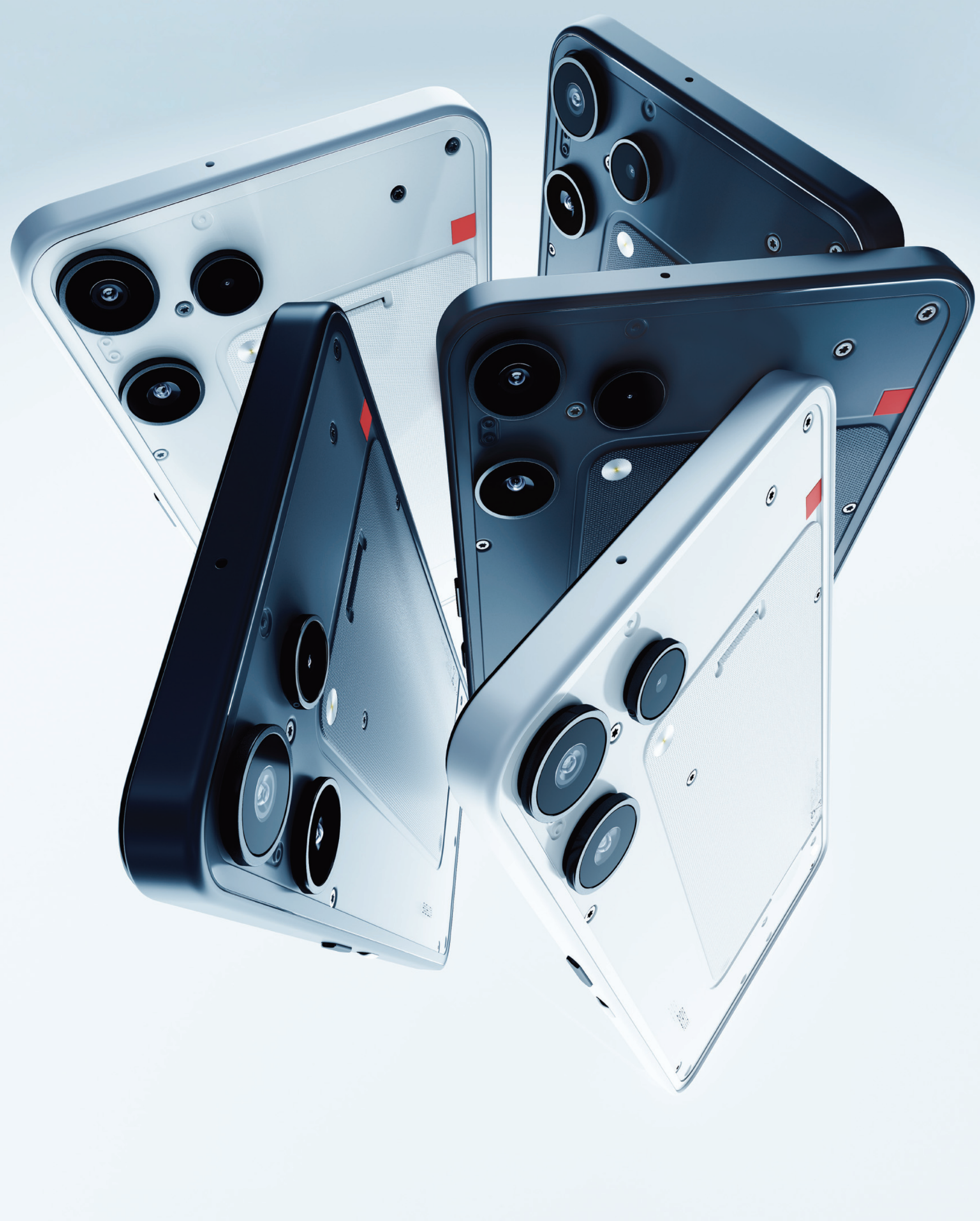

ICICI Bank | onecard

BAJAJ FINSERV | TVS CREDIT | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank ALWAYS YOU FIRST

vijay sales www.vijaysales.com | croma | Flipkart

*T&C Apply. Offer is applicable on select bank credit cards.
Pricing varies as per configuration & application offers at the retailer.

जागरूक जनता ऑन लाइन पढ़ने के लिए स्कैन करें
ई-पेपर व अन्य खबरें देखें
jagrukjanta.net

कांग्रेसराज में तो कभी सुनवाई हुई ही नहीं,

ना तो कार्यकर्ताओं की, ना ही जनता की-दीया कुमारी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी एवं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए अनेक प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया। कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों से दूरभाष पर संवाद कर त्वरित समाधान का प्रयास किया गया।

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई प्रारंभ करने का निर्णय सराहनीय है। इससे कार्यकर्ताओं के क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित फॉलोअप अत्यंत आवश्यक है, अतः सुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का सतत फॉलोअप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुनवाई में मंत्रियों के साथ पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं, जो हर दो दिन में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हर परिवादी को संतुष्ट कर वापस भेजना हमारा संकल्प है। जहां तुरंत समाधान संभव नहीं होगा, वहां उचित कारण स्पष्ट किए जाएंगे। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में कार्यकर्ताओं की सुनवाई लगभग बंद रही, जबकि भाजपा सरकार में प्रत्येक मंत्री एवं मुख्यमंत्री नियमित रूप से सप्ताह में दो बार जन एवं कार्यकर्ता सुनवाई कर रहे हैं।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई का नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, और सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्या सुनी गई। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों, अतिक्रमण, प्रशासनिक समस्याओं सहित विभिन्न विषयों से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित अधिकारियों से टिप्पणी लेकर अध्ययन कर समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, मुझे पता नहीं,

ना मैं चिकित्सक, ना वैद्य और ना ही मैं हकीम-खर्रा

उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याएं कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचें, इसी उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री द्वारा यह व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिए बिना निकाय एवं पंचायत चुनाव करवाना चाहती है तो खुलकर सामने आए। जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू किया जा सकता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना कार्य गंभीरता से कर रहा है और विस्तृत प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। प?त्रकारों के सवाल के जवाब में खर्रा ने कहा कि डोटासरा जी जब मंत्री थे, तब उनकी कोई सुनता था या नहीं सुनता था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज भाजपा के मंत्रियों की सभी अधिकारी सुनते है और उस पर कार्रवाई भी होती है। अब कांग्रेसियों के पेट में क्या दर्द है, इसका मुझे पता नहीं है। ना तो मैं चिकित्सक हूं, ना मैं वैद्य हूं और ना ही मैं हकीम हूं।

जागरूक खबरें

बाड़मेर के वीर सपूत को सम्मान, 13 को रक्षा मंत्री करेंगे मूर्ति का अनावरण,

बाड़मेर @ जागरूक जनता। भारत-पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सरहदी गांव बाखासर में 13 दिसंबर को वीर सपूत बलवंत सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होने देश की पश्चिमी रेतीली सीमा पर पाकिस्तानी सेना को कड़ी टक्कर दी थी। सरकार ने उनके बलिदान को सम्मानित किया है।. उनके पैतृक गांव बाखासर में 13 दिसंबर को एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।

यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यहां से उदयपुर, अजमेर सहित 4 नए रूट पर रोडवेज सेवा शुरू

शाहपुरा डिपो चलाएगा 4 लंबे रूटों पर बसें

जयपुर @ जागरूक जनता। शाहपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने शाहपुरा डिपो से लंबी दूरी तक बसें चलाने का निर्णय लिया है। डिपो प्रशासन ने उदयपुर, अजमेर, टोंक सहित चार नए रूटों पर बस सेवाएं संचालित कर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान करते हुए यात्रियों को राहत प्रदान की है। शाहपुरा डिपो की नई बसें 1. शाहपुरा से जयपुर होते हुए उदयपुर 2. पाचूडाला से शाहपुरा वाया 14 नंबर, जयपुर होते हुए अजमेर 3. खरकड़ी से वाया शाहपुरा होते हुए टोंक और दौसा से वाया शाहपुरा होते हुए श्रीमाधोपुर रूट पर चलेगी।

भाजपा बारां जिला की कार्यकारिणी का एलान, सात उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री बनाए

बारां @ जागरूक जनता। राजस्थान में बारां जिला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार मंगलवार को पार्टी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की और बैठक में सात उपाध्यक्ष और तीन महामंत्री तथा सात जिला मंत्री बनाये गये। जिलाध्यक्ष सिकरवार ने बताया कि नवघोषित कार्यकारिणी पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक अभियानों को गति प्रदान करेगी।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध मुख्यमंत्री शर्मा की सख्त कार्रवाई

जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरूद्ध जांच का पूर्वानुमोदन -दो सेवानिवृत्त सहित कुल 14 अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का अनुमोदन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन की निविदा में फर्जीवाड़े एवं मिली-भगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोपों के संबंध में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एवं विभाग के 05 अधिकारियों सहित कुल 06 अधिकारियों के विरूद्ध 17-ए में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान कार्यवाही का पूर्वानुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संचालित कार्यवाही की निरन्तरता में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए में विस्तृत जांच का अनुमोदन करते हुए सख्त कार्रवाई की है। निविदा कार्य से जुड़े हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार मुख्य अभियंता से लेकर अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सहित तकनीकी सदस्यों तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है ताकि सभी पक्ष उजागर हो सके और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिर्श्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोपों में एक अन्य आई.ए.एस. अधिकारी के विरूद्ध भी अखिल भारतीय सेवाए (वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील) 1969 के नियम 8 के तहत नवीन जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, के नियम 34 के तहत 05 अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। वहीं, सीसीए-नियम 16 के तहत 02 प्रकरणों में सेवा निवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी आगामी दण्डात्मक कार्यवाही हेतु किया गया।

नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव

प्रदेश में संहिताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चित-मुख्यमंत्री

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा

मजदूर और नियोक्ता दोनों के हित होंगे सुरक्षित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया।

शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है। जिससे श्रमिकों को औपचारिक रोजगार सुनिश्चित होगा। साथ ही, उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि इनमें वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान के प्रावधानों से श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संहिताओं से नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इन संहिताओं में महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन पारी में कार्य करने के साथ ही खतरनाक प्रक्रिया के कार्यों में काम करने की अनुमति दी गई है।

श्रमिक कल्याण योजनाओं का पारदर्शिता के साथ हो क्रियान्वयन

शर्मा ने अधिकारियों को श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सुधार के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 4 नई श्रम संहिताओं - मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता में 29 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। केन्द्र की इन नई श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों के पुनः प्रकाशन होने पर राज्य सरकार द्वारा पुनः नियम प्रकाषित कर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

कौन है जो बार-बार सिस्टम को धमका रहा है...

प्रदेश में 'बम थ्रेट' का रिकॉर्ड, साल 2025 में मिले 57 ईमेल, जयपुर हाई कोर्ट 40 दिनों में 4 बार निशाने पर

कोटा-जयपुर में दहशत! हाई कोर्ट से कोचिंग सेंटर तक धमकी

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

साल 2025 में अब तक राजस्थान में सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाते हुए 57 ईमेल मिल चुके हैं, जिसने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जयपुर को देश में 'बम धमकी' के मामलों में 5वें स्थान पर ला दिया है।

जयपुर @ ज्ञानेन्द्र मिश्रा। राजस्थान में 'बम धमकी वाले ईमेल' का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर हाई कोर्ट से लेकर कोटा कलेक्ट्रेट और फेमस कोचिंग सेंटर तक, प्रशासनिक दफ्तर बार-बार खाली कराने पड़ रहे हैं। कहीं जांच चल रही है, कहीं कामकाज रुक रहा है और हर धमकी के बाद वही नतीजा सामने आ रहा है। सर्च तो होता है, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिलता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन है जो लगातार पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है? कौन है जो 40 दिनों में 4 बार हाई कोर्ट को निशाना बना रहा है? कौन है जिसकी वजह से पुलिस, अदालतें और आम लोग लगातार डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं?

40 दिन में हाई कोर्ट उड़ाने की 4 धमकियां

मंगलवार सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर रजिस्ट्रार सीपीसी को एक और धमकी भरा मेल मिला, जिसके बाद तुरंत राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग खाली करा ली गई। यह पिछले 40 दिनों में हाई कोर्ट को मिली चौथी धमकी थी। धमकी मिलते ही बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब ढाई घंटे तक सघन तलाशी अभियान चला। इस दौरान सभी सुनवाई स्थगित रहीं, जिससे अदालत का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर जांच एजेंसियों ने बिल्डिंग को सुरक्षित घोषित किया, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। जयपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट आनंद शर्मा ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, 'बार-बार हो रही धमकियों से वकीलों और जजों में डर का माहौल है। हमारा काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक मेल भेजने वाले को ट्रेस नहीं कर पाई है।'

कोटा कलेक्ट्रेट और कोचिंग सेंटर भी निशाने पर

धमकी भरे मेल का दायरा केवल न्यायिक संस्थानों तक सीमित नहीं है। दो दिन पहले कोटा में भी कलेक्ट्रेट को निशाना बनाया गया। एक ईमेल में कोटा कलेक्ट्रेट और वहां के प्रसिद्ध कोचिंग सेंटरों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। कोटा के एडिशनल एसपी दिलीप सैनी के अनुसार, 'धमकी मिलने के बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं। पूरे परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। हालांकि, एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लाखों छात्र कोचिंग सेंटरों में पढ़ते हैं।'

सिस्टम को चुनौती, किसने दीं ये 57 धमकियां?

जयपुर, कोटा के अलावा उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर जैसे प्रमुख जिलों के सरकारी दफ्तरों को भी इसी पैटर्न पर धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हर बार पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने तलाशी की, लेकिन नतीजा शून्य रहा—कोई विस्फोटक नहीं मिला। डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा ने इस संगठित पैटर्न पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'मेल भेजने का पैटर्न संगठित और तकनीकी रूप से जटिल है, इसलिए पहचान में देर हो रही है। हमारी साइबर सेल की टीम आईपी एड्रेस और लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है।'

साइबर सेल हो और मजबूत

एडवोकेट विक्रम ने प्रशासन से आग्रह किया है कि फर्जी ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को और मजबूत किया जाए और प्रशासनिक स्तर पर प्रवेश निरीक्षण बढ़ाने और निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती

» तकनीकी रूप से जटिल मेल भेजने वाले संगठित गिरोह की पहचान करना।
» बार-बार हो रही धमकियों के बावजूद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बनाए रखना और लोगों के बीच विश्वास स्थापित करना।

राजस्थान को अब साइबर सुरक्षा से लेकर भौतिक सुरक्षा तक, दोनों मोर्चों पर उच्च सतर्कता बरतनी होगी। पुलिस को हर धमकी को वास्तविक खतरा मानते हुए कार्रवाई करनी होगी ताकि धमकी भरे थ्रेट के सिलसिले को जल्द से जल्द रोका जा सके।

MNIT कैंपस में घंटों छिपे तेंदुए को मशक्कत के बाद पकड़ा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) के परिसर में एक तेंदुआ (Leopard) घुसने की सूचना मिली। सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन से सतर्कता बरतते हुए परिसर में तेंदुआ देखे जाने के बाद तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने घंटो की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा।

VLTC भवन में छिपा तेंदुआ

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सघन ऑपरेशन चलाया। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि एमएनआईटी परिसर में तेंदुआ वीएलटीसी भवन में घंटो से छिपा हुआ है। इस खबर के कैंपस में फैलते ही छात्रों और टीचर में दहशत का माहौल बना हुआ है।

वन विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वही दूसरी तरफ सूचना मिलने पर तुरंत पहुंची वन विभाग की एक टीम ने अपने उपकरणों के साथ तलाशी अभियान चलाया हुआ है। साथ ही टीम ने MNIT के VLTC भवन को चारों ओर से घेर लिया है और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है।

MNIT कैंपस में रहती है एक मादा लैपर्ड तेंदुआ पूजा

चार महीने पहले, अगस्त में जयपुर में गोपालपुरा पुलिया के पास NBC कंपनी में एक तेंदुआ देखा गया था। बताया गया कि वह अपनी मां से बिछड़ गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑपरेशन के बाद पता चला कि तेंदुआ उसी रास्ते से अपनी मां के पास वापस आ गया था। उस समय, यह भी बताया गया था कि 'पूजा' नाम की एक मादा तेंदुआ पहले से ही MNIT में रहती है, और माना जा रहा है कि वह नई तेंदुआ उसकी बेटी है।

राजस्थान सरकार की क्रांतिकारी पहलः ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण युवाओं का होगा सशक्तीकरण

2 सालः नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान और विकास की नई क्रांति की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कॅरियर परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल राज्य सरकार के पिछले दो वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सरकार ने युवा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान कर राज्य को 'विकसित राजस्थान' की ओर अग्रसर कर रहा है। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। इससे शहर और गांव, सम्पन्न और कम संसाधन वाले लोगों के बीच स्थित 'डिजिटल डिवाइड'' समाप्त होगी।

अटल ज्ञान केंद्रों की विशेषताएं

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की नींव को सशक्त करने की दिशा में अटल ज्ञान केंद्र राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। प्रत्येक केंद्र में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जहां पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी। कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था से युवा ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित सेक्शन होगा, जहां अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इसके अलावा, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यर्क म भी केंद्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। साथ ही केंद्रों में ई-मित्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिक राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रत्येक केंद्र में एक प्रशिक्षित 'अटल प्रेरक' नियुक्त किया जाएगा, जो दैनिक संचालन का प्रबंधन करेगा और नागरिकों को सहायता प्रदान करेगा। यह प्रेरक स्थानीय युवा होगा, जिसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, इससे स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा। अटल ज्ञान केंद्र न केवल शिक्षा का माध्यम बनेंगे बल्कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी साबित होंगे।

पहले चरण की प्रगति

अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। फेज-1 के अंतर्गत 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1,274 केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है और इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पीछे न छूटे।

पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से मिली मजबूत साझेदारी

अटल ज्ञान केंद्रों को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1,047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति अटल ज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। 232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की इस पहल से केन्द्र की राज्यों के साथ साझेदारी और ग्रामीण विकास को मजबूती मिली है, नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। अटल ज्ञान केंद्रों की यह पहल राजस्थान सरकार के विजन 'विकसित भारत, विकसित राजस्थान' को साकार कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवा देश के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनेंगे।

पीडब्ल्यूडी के 15 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया शुभारंभ

सड़क निर्माण में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए-दीया कुमारी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी, नोएडा (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के लिए आयोजित "रोड सेफ्टी ऑडिट" ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। 15 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सभी प्रशिक्षुओं को सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने बताया कि यह 15 दिवसीय प्रशिक्षण नए नवाचारों और तकनीकों को समझने का अवसर प्रदान करेगा। दिया कुमारी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले से निर्मित सड़कों और भविष्य में बनने वाले मार्गों में सुरक्षा के बेहतर उपाय शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क निर्माण में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के अचानक सड़क पर आने से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए डिवाइडर व बेरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह ट्रेनिंग कार्यक्रम सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने ली राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक

राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की भूमिका अहम, वृद्धि हेतु बनाएं लक्ष्य आधारित कार्ययोजना

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 69 हजार 627 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवम्बर माह तक कुल 84 हजार 746 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

जीएसटी की दरों में कमी का लाभ उपभोक्ता को मिलना हो सुनिश्चित

शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के हो परमिट जारी

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक परमिट जारी किए जाएं जिससे आमजन को सुविधा होने के साथ ही, राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। शर्मा ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोडेड वाहन सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। साथ ही, इनसे राज्य सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। विभागीय अधिकारी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

क्रियान्वयन में शिक्षक, शैक्षणेत्तर कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों की है महती भूमिका

भारत को विश्वगुरू बनाने की आधारशिला है नई शिक्षा नीति 2020 - देवनानी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

उदयपुर। नई शिक्षा नीति 2020 ऐसी जीवंत दृष्टि है जो राष्ट के विकास का प्राण है। यह सिर्फ काजगी दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत को विश्व गुरू बनाने की आधारशिला है। इससे ऐसी नई पीढ़ी तैयार होगी जो राष्ट प्रथम की अवधारणा से ओतप्रोत होगी। विधासभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शैक्षणैतर कर्मचारी संघ की ओकर से आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं सेमिनार में नई शिक्षा नीति पर जन प्रतिनिधियों की सहभागिता विषय पर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए यह विचार व्यक्त किए। देवनानी ने कहा कि कस्तूरीरंगन के साथ मिलकर नई नीति को अंतिम रूप देने में उनका भी योगदान रहा है। उन्होने इसे लागू करने में शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता जताई। विशेषकर जनप्रतनिधियों की भूमिका के बारे में बोलते हुए देवनानी ने कहा कि जननप्रतिनिधि स्थानीय स्तर की आवश्यकता के अनुरूप सुझाव देते हैं जिससे नीति निर्धारण की प्रामाणिकता बढ़ती है। नई नीति में रटने और अंक प्राप्त करने के मैकाले के प्रभाव को समाप्त कर आवश्यक सुधार किया गया है।

30 करोड़ के बायोपिक घोटाले में अब खुलेगा राज!

फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को 7 दिन की रिमांड

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

उदयपुर। बॉलीवुड के गलियारों से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल वित्तीय धोखाधड़ी का मामला राजस्थान की उदयपुर अदालत में एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। बहुचर्चित बायोपिक घोटाले में आरोपी फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

30 करोड़ की कथित हेराफेरी

मामला 30 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। पुलिस अब इन 7 दिनों की रिमांड में नकली वेंडर बिल, फर्जी दस्तावेज और बड़े वित्तीय लेन-देन के पूरे 'पेमेंट ट्रेल' की गहन पूछताछ करेगी। उदयपुर पुलिस ने इस दंपति को लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर उदयपुर लाई थी।

बायोपिक बनाने का वादा

इस पूरे मामले की शिकायत इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के संस्थापक और उदयपुर निवासी डॉ। अजय मुर्डिया ने भूपालपुरा थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, विक्रम भट्ट दंपति पर डॉ। मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने के नाम पर उन्हें भारी मुनाफे का प्रलोभन देने का आरोप है। कथित तौर पर आरोपियों ने बायोपिक से 200 करोड़ तक की कमाई का झूठा दावा किया था।

मुख्य सचिव ने किया राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन का अवलोकन

राजीविका ग्रामीण उद्यमिता का सशक्त मॉडल-श्रीनिवास

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सांगानेर के ठीकरिया स्थित राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजीविका ग्रामीण उद्यमिता का एक सशक्त मॉडल है जिसके माध्यम से महिला आत्मनिर्भर बन अपने परिवार, गाँव और समाज में अपनी अलग पहचान अर्जित कर रही है । उन्होंने ब्लू पॉटरी एवं बगरू प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों के अनुभव जाने ।

मुख्य सचिव ने राजीविका के सफलता-यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि पहले जहाँ केवल सिलाई यूनिट तक ही आजीविका सीमित थी, वहीं आज महिलाएँ अनेक क्षेत्रों में लखपति दीदी बनकर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान की स्वयं सहायता समूहों की इन प्रेरणादायक कहानियों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने महिलाओं द्वारा निर्मित विविध उत्पादों की विशेष प्रशंसा भी की। साथ ही सेनेटरी नैपकिन यूनिट का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर लखपति दीदी इंदिरा देवी ने मुख्य सचिव से अपनी राजीविका यात्रा साझा करते हुए बताया कि हस्तनिर्मित लकड़ी उत्पाद कार्य कर प्रतिमाह 10,000 रुपये से अधिक की नियमित आमदनी अर्जित कर रही हैं तथा विभिन्न मेलों व प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भी भाग लेती हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक (आरजीबी) में बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट के रूप में कार्यरत मीनू शर्मा ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ ग्रामीण परिवारों तक पहुँचाया। उन्होंने बताया कि वे बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से प्रतिमाह 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन कर लगभग 45,000 की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने में बड़ा सहयोग मिला है तथा स्वंय के परिवार मैं भी सम्मान बढ़ा है। इस अवसर पर परियोजना निदेशक प्रशासन प्रीति सहित अधिकारीगण राजीविका से जुड़ी महिलाएँ उपस्थित रही।

बायर सेलर मीट से मिलेगा उत्पादों को व्यापक बाजार- गुहा

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि ग्रामीण महिलाएँ अपने कौशल एवं परिश्रम के बल पर पूर्णतः स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी बन रही हैं। राजीविका प्लेटफॉर्म ने महिलाओं में उद्यमिता को मजबूत आधार प्रदान किया है। गुहा ने बताया कि राजीविका द्वारा कृषि एंव पशुपालन संबधित व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु 'बायर सेलर मीट' का प्रारंभ किया गया है जिससे राजीविका की महिलाए अपने उत्पाद सीधे ही बड़ी कंपनियों को बेच सकेगी उन्होंने आश्वासन दिया 'बायर सेलर मीट' को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने निर्देश दिए कि राजस्थली मार्ट की तर्ज पर विभिन्न जिलों में भी महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए स्थानीय "मार्ट" स्थापित किए जाएँ, ताकि उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके। राजीविका की स्टेट मिशन डायरेक्टर नेहा गिरि ने बताया कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने कृषि, उद्यमिता, वित्तीय सेवाओं, कला एवं हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने एवं राजस्थानी पारंपरिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया।

Jagruk Janta VICHAR
/jagrukjanta /jagrukjantanews jagruk_janta
जयपुर, बुधवार
10 दिसम्बर - 16 दिसम्बर, 2025
जागरूक विचार

जागरूक जनता
www.jagrukjanta.net

सम्पादकीय

भूजल के लिए सुसंगत नीति जरूरी

पिछले कुछ वर्षों में भूजल पर भारत की निर्भरता और बढ़ गई है। देश में लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी पेय जल के स्रोत के रूप में इसी पर निर्भर हैं और सिंचाई से जुड़े लगभग दो-तिहाई कार्य जलभृतों (एक्विफर) से पूरे होते हैं। भूजल का इस्तेमाल लगातार बढ़ने के साथ ही उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ती जा रही है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि संकट अब कुछ राज्यों या प्रदूषक पदार्थों तक सीमित नहीं है। भारत अब अनेक प्रदूषकों के साथ आपात स्थिति का सामना कर रहा है और देश के कई क्षेत्रों में नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, लवणता और भारी धातुओं के लिए निर्धारित सुरक्षित सीमा पार हो गई है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश के उत्तरी राज्यों एवं क्षेत्रों में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिलों में यूरेनियम स्वीकार्य 30 पार्ट्स पर बिलियन (पीपीबी) सीमा से बहुत अधिक हो गया है। यूरेनियम का यह खतरनाक स्तर सबसे अधिक पंजाब में देखा गया है जहां मॉनसून से पहले के 53.04 प्रतिशत नमूनों और मॉनसून के बाद के 62.50 प्रतिशत नमूनों में इसकी मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई। इसके साथ ही नाइट्रेट की मात्रा भी अधिक हो गई है जो अक्सर उर्वरक के अत्यधिक उपयोग और खेतों से रसायनयुक्त पानी के बहकर जल स्रोतों तक पहुंचने का नतीजा है। रिपोर्ट में लगभग 20 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट सीमा से अधिक है और लगभग 8 प्रतिशत में बीआईएस मानक से ऊपर फ्लोराइड है। इस तरह का संदूषण (कंटैमिनेशन) प्राकृतिक और मानवजनित कारकों दोनों से उत्पन्न होता है। राजस्थान या पंजाब के कुछ हिस्सों में भूगर्भीय संरचनाएं ऐसी हैं कि भूजल स्तर गिरने पर फ्लोराइड या यूरेनियम की मात्रा बढ़ने लगती हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, अनियमित खनन और अनुपचारित सीवेज तेजी से उन हिस्सों में पानी की गुणवत्ता खराब कर रहे हैं जहां शहरों एवं संबंधित व्यवस्था का विकास तेजी से हो रहा है। अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के कारण शहरी जलभृतों में सूक्ष्मजीव संदूषण अधिक रहता है। उक्त रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि संदूषक पदार्थों की सूची में कई गांव एक साथ नजर आते हैं जो जलभृत स्तर में क्षरण का संकेत देते हैं। इसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। लाखों लोग जो जल के लिए बोरवेल पर निर्भर हैं, उनमें फ्लोरोसिस, नाइट्रेट विषाक्तता, आर्सेनिक से संबंधित बीमारियां व भारी धातुओं और यूरेनियम से जुड़े दीर्घकालिक कैंसर का खतरा अधिक रहता है। कृषि पर इसका प्रभाव भी उतना ही चिंताजनक है। दूषित भूजल न केवल उपज कम करता है बल्कि खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों के प्रदूषित होने का खतरा भी बढ़ा देता है। तमिलनाडु में छतों पर वर्षा जल संचयन से संबंधित कानून या पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक-शमन जैसे राज्य-स्तरीय प्रयास अपर्याप्त हैं। इस संकट से निपटने के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय भूजल स्वास्थ्य मिशन की आवश्यकता है। फसल विविधीकरण, उर्वरकों के नियंत्रित इस्तेमाल और मिट्टी में नमी संरक्षण जैसे कृषि जल उपाय किए जा सकते हैं। अधिक संदूषण का संकट झेल रहे गांवों के लिए विकेंद्रीकृत निस्पंदन प्रणाली जैसे सामुदायिक-स्तर पर आरओ और आयन-एक्सचेंज इकाइयां आदि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में सख्त सीवेज उपचार मानकों, रिसाव का पता लगाने वाली प्रणालियों और औद्योगिक निर्वहन निगरानी की आवश्यकता होती है।

वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं।

लोकतंत्र से संवाद : वंदे मातरम् दीर्घा

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
उप निदेशक
@jagrukjanta.net

> **राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट्र-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।**

राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को समर्पित विशिष्ट, शोधपरक और आधुनिक स्वरूप वाली दीर्घा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक चैतना के एतिहासिक तथ्यों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करती इस पहल से देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विशिष्ट बन गई है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की इस गौरवमयी सोच के साकार होने से विधान सभा का पवित्र परिसर शौर्य के भाव से आलोकित हो गया है। देवनानी ने विधान सभा में भारतीय संविधान के 22 भागों के प्रारम्भ में प्रकाशित चित्रों की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए संविधान दीर्घा और कारगिल वीरांगनाओं को समर्पित शौर्य वाटिका का भी निर्माण कराया है।

राजस्थान विधान सभा देश की पहली विधान सभा जहां वंदे मातरम् दीर्घा- देश की विधानसभाओं में राजस्थान विधानसभा अब उन विरल संस्थानों में शामिल हो गई है जहाँ वंदे मातरम् पर आधारित एक पूर्ण शोधपरक गैलरी का निर्माण हुआ है। राष्ट्र गीत के एक सौ पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार इस दीर्घा में 37 पैनलों के माध्यम से वंदे मातरम् की रचना, इतिहास, संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। वंदे मातरम्, मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का स्वरूप है। स्वदेशी आंदोलन के दौर में यह गीत जनसभाओं और आंदोलनों का प्रेरक केंद्र बनकर राष्ट्रीय भावता को संगठित करता रहा और उसी चिरंतन स्वरूप को यह दीर्घा आधुनिक माध्यमों में पुनर्जीवित कर रही है।

नए विमर्श और आधुनिकता के साथ आमजन को समर्पित- राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में यह नई दीर्घा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को नए विमर्श और आधुनिक प्रस्तुति के साथ आमजन तक पहुँचाती है। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत, दुर्लभ दस्तावेजों, वीडियो सामग्री और उस युग के सांस्कृतिक-राजनीतिक परिवेश का सजीव प्रदर्शन आगंतुकों को उस समय की अनुभूति से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य और संविधान के प्रति निष्ठा को इस दीर्घा का मूल केंद्र माना गया है, जो इसे मात्र प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनाता है।

जीवंत ज्ञान केन्द्र- 1875 में अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मुर्शिदाबाद के लालगोला में रचे गए मूल गीत की पांडुलिपि, संस्कृतनिष्ठ बंगाली पाठ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े दुर्लभफोटोग्राफ, क्रांतिकारियों के संस्मरण, पत्र, भाषण और तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण की झलक इस दीर्घा को विशेष बनाती है। युवा वर्ग, शोधार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए यह दीर्घा एक जीवत जान केन्द्र के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।

स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थान विधानसभा ने इतिहास को स्थिर रूप में नहीं, बल्कि जीवंत एवं संवादमय रूप में प्रस्तुत किया है। संग्रहालय का यह विस्तार ऐसी सोच को दर्शाता है जिसमें राजनीति केवल नीतियाँ और बहसों तक सीमित न रहकर संस्कृति, इतिहास और नागरिक चेतना को भी समान महत्व देता है।

इतिहास को महसूस कराने वाली दीर्घा वंदे मातरम् दीर्घा- वंदे मातरम इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक आदर्शों का ऐसा विशिष्ट संगम बनकर उभर रही है, जो भारतीय लोकतंत्र की गहराई और राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता को नई पीढ़ियाँ तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध होगी। राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम् दीर्घा केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान को जोड़ने वाला समकालीन सेतु है। डिजिटल इंटरैक्टिव पैनलों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संयोजन ने इसे पारंपरिक संग्रहालयों की सीमाओं से आगे पहुँचा दिया है। इसे देखने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं संघर्षों और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में न केवल शोधार्थियों के लिए बल्कि उन युवाओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान साबित होगी जो इतिहास को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं।

करोडों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिम्ब- वंदे मातरम् दीर्घा राष्ट्रगीत के इतिहास को समेटे हुए है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना को जन भाषा में प्रस्तुत करती है। दीर्घा के प्रत्येक पैनल में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, आंदोलनकारी ऊर्जा के अंश और राष्ट्रनिर्माण में काला-साहित्य की भूमिका के अध्याय सजीव हो उठे हैं। यह दीर्घा उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक स्मृति का प्रतिबिंब है जिन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध करते हुए वंदे मातरम् को अपनी आवाज का आधार बनाया था। आधुनिक भारत की युवा पीढ़ी जब इस दीर्घा में प्रवेश करती है, तो वह केवल इतिहास नहीं देखती वह अपने भीतर राष्ट्रभावना की एक नई समझ का जन्म अनुभव करती है।

लोक संस्कृति पथ - राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को कला, संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक प्रतीक और ऐतिहासिक धरोहरों के भित्ति चित्रों से उकेरा गया है। यह लोकक संस्कृति से परिचय कराने वाला पथ बन गया है।

आखर आखर झरे उजियार

ईश्वरप्राप्ति में बड़ा अवरोध अभिमान

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

गोपाल प्रभाकर
पत्रकार
@jagrukjanta.net

यह तो सभी जानते हैं कि समुद्र में बूंद समाहित रहती है, लेकिन कोई कोई बिरला गुण ग्राहक ही समझता है कि बूंद में भी सागर निहित होता है। ये बात ख़ास नज़र और विशेष नजरिये वाले लोग ही पहचान सकते हैं।

भगिनी निवेदिता ने अपने संस्मरण लिखते हुए अवगत कराया कि स्वामी विवेकानन्द हमारे प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान दृष्टांत और लघु कथाओं के माध्यम से करने में माहिर थे। कठिन विषयों को सरल बनाने की कला उन्हें आती थी। एक बार व्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्ति को लेकर चर्चा के दौरान मैं अधीर हो गई। मुझ से मेरा मैंपन नहीं छूट रहा था। ये मेरे सोच के बाहर की बात लग रही थी। मैं अनंत मैं विलीन होने की बात को नकार रही थी।व्यष्टि के समष्टि में विलय की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी।इस विचार से मैं कुछ हद तक डरी हुई थी।विवेकानंद धैर्य पूर्वक सहज भाव से मुझे सुनते रहे। फिर गुरु गम्भीर वाणी में बोले,जल की एक बूंद सागर में पड़ते ही तुम्हारी तरह विचलित हो गई और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की दुहाई देने लगी।समंदर ने तब उसे समझाया, तुम नाहक परेशान हो रही हो।मुझे तो इस अधीरता की कोई वज़ह नज़र नहीं आती।मेरे साथ जुड़ कर तुम अपने स्वजातीय बहन बंधुओं से मिल गई हो। समस्त बूंदों के एकत्र होने पर जो एकाकार निर्मित हुआ वही तो समुद्र है। फिर भी तुम्हारी स्वतंत्र होने की इच्छा है तो व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। मैं एक उपाय बताता हूँ। सूर्य की किरणों के सहारे ऊपर उठ कर बादल का हिस्सा बन जाओ। फिर आशीर्वाद स्वरूप बरस कर प्यासी धरती पर उतर जाओ।

सिस्टर निवेदिता ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए बताया कि स्वामी जी की इस मिसाल से मेरे मन की व्याकुलता दूर हो गई । साथ ही, मेरा अज्ञान भी जैसे तिरोहित गया। व्यष्टि के अकिंचन रूप में मुझे अब विराट के दर्शन होने लगे। जब व्यक्ति समष्टि भाव धारण कर लेता है तो उसका अहम वयम में तब्दील हो जाता है। उसका मैं (अहम) हम (वयम) रूप में परिणत हो जाता है।

कबीर की पँक्तियाँ याद आती है...
हेरत हेरत है सखी,रहा कबीर हिराय,
बूंद समानी समुन्द में, सो कत हेरी जाय!

पुतिन की भारत यात्राः रणनीतिक स्वायत्तता का दम

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

दिलीप शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की पहली भारत यात्रा की हर तरफ चर्चा हुई। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक ऐसे रिश्ते की मजबूती का प्रदर्शन किया है जो तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात और मौजूदा परिस्थितियों में भी अडिग रहा है जबकि भारत और रूस दोनों ही अमेरिका के दबाव से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वयं पुतिन की अगवानी करना और एक ही वाहन में दोनों नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना, दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है। राष्ट्रपति भवन में भी पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया। ये तमाम बातें भारत-रूस संबंधों में पिछले कई दशकों से चली आ रही स्थिरता परिलक्षित करती हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पुतिन की यह भारत यात्रा वाकई किसी ठोस लाभ में तब्दील हो पाई?

रूस इस समय एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिमी देश पुतिन को दरकिनार करने में लगे हैं और उनका देश बढ़ते आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर शांति वार्ता भी जटिल दौर से गुजर रही है। मगर इन सब के बीच भारत जैसे मजबूत एशियाई देश की यात्रा पुतिन और रूस दोनों के लिए एक बड़ी ताकत का संचार करने वाली है। रूस से तेल खरीदने के फैसले के परिणामस्वरूप अमेरिकी शुल्कों का सामना कर रहा भारत भी अमेरिका के साथ अपने बिगड़े संबंध साधने में जुटा है। मगर भारत ने पुतिन की इस यात्रा को वैश्विक मामलों में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के तौर पर पेश किया। मोदी का यह बयान कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है, शायद यूक्रेन में पुतिन की कार्रवाई की एक अप्रत्यक्ष आलोचना है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना इस संदेश को और मजबूती से रेखांकित करता है।

मगर इस रणनीतिक स्वायत्तता की असली परीक्षा अभी होनी बाकी है। पहली बात यह कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अभी कोई शक्ल नहीं ले पाया है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन चीन के साथ लगातार बातचीत कर रहा है जबकि वह रूस के साथ उसके (चीन) गहरे आर्थिक संबंधों से अच्छी तरफ वाकिफ है। दूसरी बात यह है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर होती दिख रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत यात्रा करने की योजना रद्द कर दी है। भारत को इस साल चार देशों के 'क्वाड' शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी।

यह सवाल भी मुंह बाए खड़ा है कि क्या पुतिन की यात्रा से भारत को तत्काल अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति करने में मदद मिली है। मगर भविष्य के लिए कई दावे किए गए हैं जिनकी बुनियाद मुख्य रूप से 2024 में मोदी की रूस यात्रा के दौरान रखी गई थी। पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने, पांच सदस्यीय यूरेशियाई आर्थिक संघ पर बातचीत जारी रखने, पुतिन की तरफ से यूरोपीय संघ को तीखी प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय मुद्राओं और डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल से व्यापार को सक्षम बनाने जैसी कई प्रमुख बाते रहीं। भारत और रूस में व्यापार, परिवहन और नागरिक परमाणु सौदों में सहयोग से जुड़े समझौते भी हुए। रूस की छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में विशेषज्ञता को देखते हुए ये समझौते काफी महत्त्वपूर्ण हैं। भारत के दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच 'श्रमिक आदान-प्रदान समझौता' भी अहम है जिसके तहत इस दशक के अंत तक 30 लाख नौकरियों के लिए लोगों की कमी पूरी करने के लिए कुशल भारतीय श्रमिक रूस भेजे जाएंगे।

हालांकि, पुतिन को दो दिवसीय यात्रा में कोई रक्षा समझौता नहीं हुआ। रूसी एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के अतिरिक्त स्क्वाड्रन के लिए भारत के अनुरोध का कोई उल्लेख नहीं हुआ और न ही पांचवीं पीढ़ी के सुखोई एसयू-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का ही जिक्र हुआ। भारतीय वायु सेना को ऐसे किसी सौदे से अपनी ताकत बढ़ाने और अहम कमियों को दूर करने में मदद मिलती। मौजूदा रक्षा साजो-सामान के लिए पुर्जों की उपलब्धता (जो भारत की एक बड़ी चिंता रही है) का संयुक्त बयान में जरूर उल्लेख हुआ। इसमें भारत में संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई। हालांकि, भारत को इस बात से उत्साहित होना चाहिए कि इस बैठक से निकले नतीजों पर पश्चिमी देशों ने कोई बड़ा विरोध नहीं जताया है।

ओपिनियन

ट्रांसजेंडर समुदाय : पहचान और अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है। राजस्थान में ऋ्र्ज्ञ्र्पत्रिका और Transgender Utthan Kosh जैसी नीतियाँ और कोष हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तक पहुँचने में अनेक बाधाएँ हैं। यह दिखाता है कि अधिकार केवल कानून या घोषणाओं से नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की संवेदनशीलता से मिलते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय सदियों से मौजूद है। ये लोग लंबे समय से समाज के एक किनारे पर खड़े हैं। आज तक उनकी पहचान को नकारा जाता रहा है उनके अधिकारों को केवल कागज़ों में सीमित रखा गया है और उनके अस्तित्व को अक्सर दबाया गया है । स्कूलों में ताने, कॉलेजों में उपेक्षा, कार्यस्थलों पर भेदभाव, सार्वजनिक जगहों पर हिंसा और अपने ही घर में अस्वीकार होना, यह उनके जीवन की रोज़मर्रा की हकीकत है। हर बार उन्हें अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इनको कभी कभी धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मान मिलता है पर ज्यादातर सभ्य समाज में इनको उपहास और कलंक का सामना ही करना पड़ा। समाज में उनका स्थान हमेशा विवादित रहा है। यही कारण है कि इस समुदाय को न केवल अपनी पहचान, बल्कि अपने अधिकारों और न्याय के लिए भी लगातार संघर्ष करना पड़ता है।

मणिमाला शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA बनाम भारत सरकार मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। यह फैसला केवल पहचान का दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में समान अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इस फैसले ने ट्रांसजेंडर लोगों को संविधान के तहत समान नागरिक अधिकारों का आश्वासन दिया।पर इन सब के बावजूद यह समुदाय भेदभाव का दंश झेल रहा है । इसके बाद केंद्र और राज्यों ने इस समुदाय के कल्याण और अधिकारों के लिए बोर्ड और योजनाएँ लागू करना शुरू किया। राजस्थान में भी राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (RTWB) का गठन किया गया। RTWB राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आता है और इसमें सरकारी अधिकारी और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। बोर्ड का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना, समुदाय की वास्तविक जरूरतें सुनना और उन्हें समाज में समान अवसर दिलाना भी है।

नीतिगत आधार और योजनाएँ

राजस्थान सरकार ने 2021 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए Transgender Utthan Kosh (उत्थान कोष) की स्थापना की। इस कोष के तहत लगभग ?8.98 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोग व्यवसाय या स्वरोजगार की शुरुआत कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा, रोजगार, आवास, पहचान पत्र और सामाजिक समावेशन के उपाय किए जाएंगे। सरकारी आवासीय योजनाओं में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 2% आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया। सिद्धांत और नीतिगत स्तर पर यह सब एक मजबूत आधार बनाता है। योजना, बजट और बोर्ड का अस्तित्व यह दर्शाता है कि प्रशासन ने इनके उत्थान के लिए रूपरेखा तैयार कर दी है। लेकिन यह सारी योजनाएं और दावे केवल शुरुआती कदम ही साबित हुए हैं । क्योंकि इन योजनाओं और बोर्डों की नीतियों का क्रियान्वयन जमीन स्तर पर प्रभावी तरीके से कभी लागू हो ही नहीं पाया ।

RTWB- संरचना और कार्यप्रणाली

वैसे देखा जाए तो राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (RTWB) की भूमिका केवल योजनाएँ बनाने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविक जरूरतों को नीति निर्माण में शामिल करना,स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना,स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के लिए कोष का प्रबंधन करना तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी आवाज़ को निर्णय प्रक्रिया में स्थान देना है । इस प्रकार RTWB प्रशासन और समुदाय के बीच एक पुल का काम करता है। बोर्ड नीतिगत रूप से तो तैयार है, लेकिन इसकी और ट्रांस समुदाय की वास्तविक चुनौतियाँ अब भी बरकरार हैं। ट्रांस समुदाय के उत्थान के दावों की हक़ीक़त खोखली साबित हुई हैं।

जमीनी हकीकत और कठिनाइयाँ

नीति और योजनाएँ तो मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को आज भी कई अड़चनें झेलनी पड़ती हैं। चूँकि आज भी समाज में उनको कोई सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता। इसलिए सामाजिक व्यवस्था के तहत उनका बहिष्कार ही किया जाता है। इसके अलावा उनको एनी कई मुसीबतों और परेशानियों से जूझना पड़ता है जैसे

- **पहचान और दस्तावेज़ीकरण -** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज़ बनवाना चुनौतीपूर्ण है। कई बार अधिकारी प्रिं या को जटिल बना देते हैं और इससे उनके अधिकारों का उपयोग मुश्किल हो जाता है।
- **रोजगार और शिक्षा-** सामाजिक भेदभाव और परिवार/समाज की अस्वीकृति के कारण शिक्षा और रोजगार में अवसर सीमित रहते हैं। स्वरोजगार कोष की मदद तक पहुँच भी कठिन होती है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता अधूरी रह जाती है।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा-** सरकारी अस्पतालों में भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आज भी बड़ी चुनौती है। योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन और जागरूकता की कमी समुदाय को लाभ लेने से रोकती है। ट्रांस समुदाय के लिए कार्यरत एक चिकत्सक डॉ अरविंद ने बताया की हॉस्पिटलों या अन्य कई स्थानों पर इन लोगों के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है । बाजार, मॉल्स, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर ये लोग वाशरूम तक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी और अधिकारों की तो बात छोड़ ही दी
- **सामाजिक बहिष्कार और कलंक-** परिवार और समाज में अस्वीकृति, कलंक और डर के कारण ट्रांसजेंडर लोग अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज़ नहीं उठा पाते। यह उनके आत्म-सम्मान और सामाजिक भागीदारी को कमजोर करता है
- **कानूनी बाधाएँ-** 2019 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम भले मौजूद हो, लेकिन प्रशासनिक अड़चनें और जागरूकता की कमी के कारण न्याय अधूरा रह जाता है।

नीति और समाज की जिम्मेदारी

- ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और योजनाएँ तभी प्रभावी होंगी जब समुदाय की वास्तविक आवाज़ को नीतियों में शामिल किया जाए।योजनाओं का नियमित और पारदर्शी रिं यान्वयन हो।
- सरकारी अधिकारी संवेदनशील प्रशिक्षण लें और भेदभाव रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।सिर्फ बजट या योजना बनाना पर्याप्त नहीं। आवश्यकता है संवेदनशीलता, जागरूकता और निष्पक्षता की। प्रशासन और समाज दोनों की भागीदारी जरूरी है।

जमीनी अनुभव को समझना

- ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी केवल उनके अधिकारों का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और लोकतंत्र की मजबूती का पैमाना भी है। जब तक समाज, परिवार और प्रशासन उनके संघर्ष को समझकर सहयोग नहीं करेगा, तब तक यह समुदाय न्याय पाने के लिए लगातार लड़ता रहेगा।
- उनकी रोजमर्रा की चुनौतियाँ, सामाजिक कलंक, पहचान और दस्तावेज़ीकरण की बाधाएँ, स्वास्थ्य व शिक्षा तक सीमित पहुँच यह दिखाती हैं कि नीतिगत घोषणाओं के बावजूद असली बदलाव अभी दूर है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। बोर्ड और कोष ने एक आधार तो बनाया, लेकिन न्याय और समान अवसर तब तक अधूरे रहेंगे जब तक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा और समाज में संवेदनशीलता नहीं आएगी।

पंचांग

ज्योतिर्विद् अक्षय शास्त्री
साकेत पंचांग, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

जागरूक जनता पंचांग, नक्षत्र, तिथि, चौघड़िया

सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथि

बुधवार, 10/12/2025

सूर्योदय : 07:09 **सूर्यास्त :** 17:30 **चन्द्रोदय :** 23:18 **चन्द्रास्त :** 11:43 **शक सम्वत :** 1947 विश्वावसु **विक्रम संवत् :** 2082 कालयुक्त **अमान्ता महीना :** मार्गशीर्ष **पूर्णिमांत :** पौष **सूर्य राशि :** वृश्चिक **चन्द्र राशि :** सिंह **पक्ष :** कृष्ण **तिथि :** षष्ठी, 13:52 तक **वार :** बुधवार **द्रिक-वैदिक ऋतु :** हेमंत **द्रिक-वैदिक अयन :** दक्षिणायन **कलियुग :** 5126

नक्षत्र, योग, करण

नक्षत्र : मघा, 26:43 तक
योग : वैधृति, 12:40 तक
प्रथम करण : वणिजा, 13:52 तक
द्वितिय करण : विष्टि, 25:49 तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त	05:14 ए एम से
प्रातः सन्ध्या	05:41 ए एम से
अभिजित मुहूर्त	कोई नहीं
विजय मुहूर्त	01:58 पी एम से
गोधूलि मुहूर्त	05:22 पी एम से
सायाह्न सन्ध्या	05:25 पी एम से
अमृत काल	12:18 ए एम, दिसम्बर 11 से
निशिता मुहूर्त	11:47 पी एम से
रवि योग	07:03 ए एम से

निवास और शूल
दिशा शूल : उत्तर में
राहु काल वास दक्षिण-पश्चिम में
होमाहुति : गुरू
चन्द्रवास : पूर्व

चौघड़िया

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
लाभ	: 07:08 - 08:25	उद्वेग	: 17:29 - 19:11
अमृत	: 08:25 - 09:43	शुभ	: 19:11 - 20:54
काल काल वेला	: 09:43 - 11:01	अमृत	: 20:54 - 22:36
शुभ	: 11:01 - 12:18	चर	: 22:36 - 00:19
रोग वार वेला	: 12:18 - 13:36	रोग	: 00:19 - 02:01
उद्वेग	: 13:36 - 14:53	काल	: 02:01 - 03:43
चर	: 14:53 - 16:11	लाभ	: 03:43 - 05:26
लाभ	: 16:11 - 17:29	उद्वेग	: 05:26 - 07:08

अमृत, शुभ, लाभ और चर को शुभ चौघडिया माना जाता है एवं उदवेग, काल एवं रोग को अशुभ चौघडिया माना जाता है।

आज षष्ठी

आज कौन सा कार्य करें

षष्ठी : यात्रा, पितृ कर्म, मंगल कार्य, संग्राम, शिल्प, वास्तु, भूषण के लिए शुभ है।

बुधवार को क्या करें

बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। यह भगवान गणेश और दुर्गा का दिन है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए।
ये कार्य करें :- सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। बुधवार को दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और नैऋय दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन जमा किए गए धन में बरकत रहती है। मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उचित है। ज्योतिष, शेयर, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है।
यह कार्य न करें:- उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें। बुधवार को धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है।

नोट : शुक्ल पक्ष में एक से पंचमी तक तिथियां अशुभ कही गई हैं, क्योंकि इन तिथियों में चंद्रमा क्षीण बल होता है और चंद्र बल उन दिनों नहीं रहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक तिथियों में चंद्र बल क्षीण होने से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

राशिफल

मार्गशीर्ष, कृष्ण, षष्ठी, 2082 बुधवार, 10 दिसम्बर - 16 दिसम्बर, 2025

मेष [चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ]
रिश्तेदारों के कारण कुछ तनाव हो सकता है। अपशब्दों का बिल्कुल प्रयोग न करें। विद्यार्थी करियर को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। दूसरों की सहायता करके आपको आत्मसन्तुष्टि महसूस होगी।

तुला [रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते]
आप लोगों से सम्मान की अपेक्षा रखेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकती है। रुचि पूर्ण कार्य करने के अवसर मिलेंगे।

वृषभ [ई,उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो]
घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। दोपहर के बाद आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भौतिक भोग-विलास का भरपूर आनन्द लेंगे।

वृश्चिक [तो,ना,नी, नू,या,यी,यू]
आपको सकारात्मक बने रहना चाहिये। बच्चे पढ़ाई के बजाय दूसरे कार्यों में समय अधिक व्यर्थ करेंगे। दोस्तों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर चर्चा हो सकती है। शाम के समय कहीं घूमने जा सकते हैं।

मिथुन [क, की,कु,घ, ड,छ,के,को,ह]
बड़े व प्रभावशाली लोगों से मिलना पड़ सकता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुये नये कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। महिलाओं को अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

धनु [ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढ, भे]
आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ नहीं आयेगी इसीलिये बिना माँगे किसी को सलाह न दें। पुराने विवाद दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं। आप कोई नया कार्य आरम्भ करने से बचें।

कर्क [हि, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो]
पुराने रुके हुये कार्य प्रारम्भ हो सकते हैं। नये व्यापारिक अनुबन्ध कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। पिता के साथ चर्चा व उनका आशीर्वाद लेना उत्तम होगा।

मकर [भो, जा,जी, जू, खा, खू, गा, गी,]
आपके प्रेम सम्बन्ध अत्यन्त मधुर रहने वाले हैं। सामाजिक सम्पर्क में वृद्धि होगी। तनाव के बावजूद कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। आप कई लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

सिंह [मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टु, टे]
महत्वपूर्ण कार्यों को एक-दो दिन के लिये टालना हितकर होगा। पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। आपके ऊपर कार्यभार की अधिकता रहेगी। एक ही काम को बार-बार करना पड़ सकता है।

कुंभ [गू, गे, गो,सा, सी, सू, से, सो, दा]
पैतृक सम्पत्ति मामलों के उलझने की सम्भावना बन रही है। गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। वकालत की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को नया कुछ सीखने को मिलेगा।

कन्या [टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो]
फाइनेन्स से जुड़े मामलों के लिये दिन बहुत अच्छा है। विवादित मामलों में आपकी विजय हो सकती है। आपके खर्चों में कमी आयेगी।

मीन [दी, दू, थे, झ, ञ, दे, दो, चा, चि]
अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये खानपान और योग पर ध्यान दें। प्रेमी जन को आज मूल्यवान उपहार दे सकते हैं।

आचार्य राजेश शास्त्री, जयपुर

तीन दिवसीय द्वितीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे 100 से ज्यादा देश

पारंपरिक चिकित्सा को कारगर करेगा शिखर सम्मेलन

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर @ ज्ञानेन्द्र मिश्रा। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में 17-19 दिसम्बर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन से पहले एक पूर्वावलोकन पर महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बनीपार्क, जयपुर के संस्थान प्रभारी सहायक निदेशक डॉ. बी. आर. मीणा ने बताया कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को प्रोत्साहन देगा तथा शिखर सम्मेलन वैज्ञानिक सत्यापन, डिजिटल स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा। 2023 में गुजरात में आयोजित पहले सफल आयोजन के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की भारत मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा की यह शिखर सम्मेलन मानवता के स्वास्थ्य,खुशी और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत के "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः" के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय "संतुलन बहाल करनाः स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास" है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री, नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य नेता, शोधकर्ता, विशेषज्ञ उद्योग प्रतिनिधि और चिकित्सक एक साथ आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि कल दिल्ली मे आयोजित प्रेस वार्ता मे आयुष मंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर ज़ोर देतेहुए कहा कि आयुष प्रणालियाँ - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी - सदियों से लोगों की सेवा करती रही हैं और आज समग्र स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय समाधान के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साझेदारी में गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।

आगामी शिखर सम्मेलन की योजना बनाने में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की संभावना है तथा विश्वास व्यक्त किया कि शिखर सम्मेलन से प्राप्त विचार-विमर्श और सहयोग विश्व को स्वास्थ्य सेवा के अधिक समग्र, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाएंगे।शिखर सम्मेलन के विचार-विमर्श के एक भाग के रूप में, "अश्वगंधाः पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक प्रभाव तक - अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण" शीर्षक से एक केंद्रित कार्यक्रम 17-19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह सत्र अश्वगंधा की वैज्ञानिक समझ को मज़बूत करने के लिए प्रमुख शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा। चर्चाओं में इसके एडाप्टोजेनिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव और इम्यूनोमॉड्युलेटरी गुणों पर समकालीन साक्ष्यों पर प्रकाश डाला जाएगा, साथ ही पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त विचारों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। सुरक्षा आकलन पर ज़ोर देते हुए, इस सत्र का उद्देश्य उच्च- गुणवत्ता वाले, साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा उत्पादों की वैश्विक स्वीकृति को और बढ़ावा देना है। पूर्वावलोकन कार्यक्रम 9-10 नवंबर 2025 को आयोजित राजदूतों के स्वागत समारोह के बाद आयोजित किया जा रहा है, जहाँ राजनयिकों को भारत-डब्ल्यूएचओ सहयोग और शिखर सम्मेलन के वैश्विक महत्व से अवगत कराया गया था।

विद्याधर नगर-किशन बाग में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

सड़कों पर घूम रहे 41 बेसहारा गौवंश रेस्क्यू, 2 अवैध डेयरियाँ सील

हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजे गए सभी गौवंश

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा ने विद्याधर नगर एवं किशन बाग क्षेत्र में बेसहारा एवं निराश्रित गौवंश को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर तथा उपायुक्त सीमा शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम डॉ. योगेश शर्मा एवं डॉ. राकेश कलोरिया ने पूरे क्षेत्र में सघन निरीक्षण करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान सड़कों, गलियों और आवासीय इलाकों में घूम रहे 41 बेसहारा गौवंश को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजा गया। टीम ने मौके पर मौजूद पशुओं की स्थिति की जांच की तथा परिवहन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया। इसी कार्रवाई के तहत क्षेत्र में संचालित दो अवैध डेयरियों पर भी निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर बंद कराया। टीम ने डेयरी संचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध संचालन पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सीमा शर्मा ने बताया कि आवासीय इलाकों और मुख्य सड़कों पर घूमते बेसहारा गौवंश न केवल यातायात बाधित करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी बनते हैं। इसी को देखते हुए निगम द्वारा ऐसे क्षेत्रों में नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शहर में यातायात सुचारू रहे और पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। निगम आयुक्त डॉ गौरव सैनी ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। लक्ष्य है कि शहर को बेसहारा पशु समस्या से मुक्त किया जाए और सभी गौवंश को सुरक्षित पुनर्वास केंद्रों तक पहुँचाया जाए।

बियानी कॉलेज में एनएसएस शिविर में कैरियर मार्गदर्शन, योग सत्र और नुक्कड़ नाटक आयोजित

जयपुर @ जागरूक जनता। बियानी कॉलेज ऑफ़ साइंस एंड मैनेजमेंट में आयोजित एनएसएस सात-दिवसीय कैंप के तहत ज्ञान, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। शिविर की शुरुआत ऊर्जात्मक योग सत्र और प्रेरक एनएसएस गीत के साथ हुई, जिसने वॉलंटियर्स में अनुशासन, एकता और टीमवर्क की भावना को मजबूत किया। योग सत्र के दौरान छात्रों ने शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति को बढ़ाने वाले कई आसन और श्वास तकनीकें सीखीं। शिविर का संचालन एनएसएस इंचार्ज डॉ. निखिल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज में फिजिक्सवाला टीम द्वारा वॉलंटियर्स के लिए एक विशेष कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने छात्रों को सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह सत्र छात्रों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी साबित हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने एक सरकारी स्कूल में जाकर "स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत" विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से छात्रों ने स्वच्छता, हाइजीन और युवाओं की जिम्मेदारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया, जिसे बच्चों ने उत्साहपूर्वक देखा और सराहा। कैंप की इन गतिविधियों ने छात्रों में जागरूकता, आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को और प्रबल किया, जिससे एनएसएस शिविर के उद्देश्यों की सार्थक पूर्ति होती दिखाई दी।

'बदलाव' भिक्षुक पुनर्वास गृह के तृतीय स्थापना दिवस पर हवन व प्रसादी आयोजित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। सामाजिक सेवार्थ अग्रणी संगठन सक्षम सामाजिक उत्थान एवं विकास संस्थान द्वारा संचालित भिक्षक पुनर्वास गृह सांगानेर जयपुर के स्थापना दिवस पर बीते दिनों भव्य हवन व प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों, रहवासियों और स्टाफ ने मिलजुल कर 1100 से भी अधिक आहुतियों के साथ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन जयपुर जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में तीन वर्ष से पुनर्वास गृह का संचालन जयपुर के सांगानेर इलाके में किया जा रहा है। यहां 700 से ज्यादा लोगों को परिवार के साथ पुनर्वासित किया जा चुका है, 300 से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों से जोड़ा गया है। अनेकों लोगों को यथा संभव ईलाज करवाकर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक कर समाज की मुख्य धारा में लाया जा चुका है। संस्थान की सचिव ईवादीप सक्सेना ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित निर्धन निराश्रित बुजुर्ग दिव्यांग जनों का यह निःशुल्क आवास जहां समय समय पर समाज के प्रबुद्ध जन जुड़ कर सेवा की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

'वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी' का उद्घाटन

उदयपुर @ जागरूक जनता। पिछले चार दशक से दिव्यांगजन की निःशुल्क चिकित्सा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत देश के अग्रणी नारायण सेवा संस्थान के माली कॉलोनी स्थित बहुमंजिला नव परिसर ' वर्ल्ड आफ ह्यूमैनिटी' का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश-विदेश से आए संस्थान सहयोगी,भामाशाह एवं सेवा मनीषी केन्या से कुंवर भाई, यूके से प्रकाश नदरानी, हरीश श्रीधर यूएसए से लीना दवे, तंजानिया से भरत भाई परमार और गुड़गांव से डॉ. सुरेंद्र प्रसाद गर्ग, मुंबई से चंद्रकांत भाटिया, दिल्ली से डी.सी जोशी की पावन मौजूदगी रही। संस्थान संस्थापक पद्मश्री अलंकृत कैलाश 'मानव' सह संस्थापिका कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल,जगदीश आर्य, देवेंद्र चौबीसा, पलक अग्रवाल, महर्षि अग्रवाल ने प्रातः शुभ मुहूर्त में यज्ञात्मक हवन कर विश्व में सुख - शांति की कामना की। भवन का निर्माण कार्य 8 फरवरी 2020 को आरंभ हुआ था। करीब 2 लाख 40 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित भवन में तीन भूतल सहित 11 मंजिल है। भवन में 450 बेड के अस्पताल, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आर्टिफिशियल लिंब वर्कशॉप, फिजियोथैरेपी, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, भोजन शाला सहित दिव्यांगों की सेवा के सभी आवश्यक प्रकल्प एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे।

भारत विकास परिषद ने किया विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। भारत विकास परिषद अंबाबाड़ी शाखा द्वारा प्रति वर्ष की भांति स्वेटर वितरण का कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड नंबर 2 मुरलीपुरा पर 263 बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, राजेश अग्रवाल, महेश कुमावत, रमेश श्यारा, लोकचन्द हरिरामानी, नगेन्द्र वशिष्ठ, कमलेश शर्मा, महावीर भट्ट, रमेश चौधरी, पंडित राजेश शास्त्री, सुनील पटवारी, मातादीन अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतीक शर्मा, सुभाष कुमार गुप्ता, प्रदीप शर्मा, एम डी कटारिया, राजेश अग्रवाल रमेश श्यारा, डॉ आर एस ग्रोवर, महावीर भट्ट, डॉ शकुंतला शर्मा, बी एल छीपा, श्याम सुंदर खत्री, डॉ गुंजन शर्मा, सीए गीतिका शर्मा, रमेश चौधरी, विक्रांत अग्रवाल, पंडित राजेश शास्त्री, शिव भगवान गोयल संजीव ठाकुर, डॉ कपिल मावंडिया, एस एन विजयवर्गीय, महेंद्र सिंह शेखावत का आर्थिक सहयोग रहा।

सोबर का जरसी वितरण कार्यक्रम जारी

जर्सी-जैकेट पाकर खिले छात्रों के चेहरे

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। बीते दिनों सोसाइटी आफ ब्राह्मण एक्ज्यूकेटिवस् राजस्थान (सोबर) द्वारा राजकीय स्कूलों, ब्राह्मण छात्रावासों मे छात्र छात्राओं को जरसी /जैकेट वितरण का कार्य क्रम के तहत इस बर्ष पंचम चरण में, राजस्थान ब्राह्मण वैष्णव समाज छात्रावास शिप्रा पथ मानसरोवर में सांयकाल 6.30 से 8.00 बजे तक किया गया। कार्य क्रम में सोबर अध्यक्ष डॉ शिव गौतम, राज्यश्री गौतम, सोबर के महासचिव इं. आर सी शर्मा, सोबर के डायरेक्टर सुशील पारीक एवं कमलेश शर्मा सोबर के वरीष्ठ सदस्य इं. अशोक शर्मा, सुरेश शर्मा एवं अर्चना शर्मा उपस्थित रहकर अपने हाथो से छात्रावास के सभी छात्रों को गरम जैकट वितरित किये सभी ने हाथों हाथ वही पहने जिनकी क्वालिटी देखकर सभी छात्र काफी प्रसन्न हुए सभी ने सोबर द्वारा उपलब्ध कराये जैकट / कोट पहनकर ग्रुप फोटो खिचवाई। कार्यक्रम की शुरूआत में छात्रावास के सचिव बंकट लाल वैष्णव और कोषाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने सोबर के पदाधिकारियों का साफा एवं दुपट्टा पहना कर स्वागत किया।सोबर के अध्यक्ष डॉ शिव गौतम जी ने अपने उद्बोधन में सभी छात्रों को ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मणों के संस्कारों को अपनाने जैसे शाकाहारी बने रहना, अपने कमरे या घर में अपने इष्ट देव की फोटो मूर्ति रख कर प्रतिदिन दिन की शुरुआत उनकी प्रार्थना पूजा से करे, आवश्यक कुछ मन्त्र बोले जो उन्होंने बोल कर बताये,जनेऊ धारण करने की सलाह देते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में बताया , मनु स्मृति के बारे में सही जानकारी दी , श्रीमती राज्यश्री गौतम ने मनुस्मृति मे वर्णित चार वर्णो यदि किसी एक व्यक्ति में समाहित हैं तो वो है माँ। गौतम ने अपनी स्वरचित कविता पाठ कर बताया, किस तरह माँ में चारों वर्ण समाहित है माँ कैसे चारों वर्णो का कार्यपालन स्वयं माँ समय समय पर करती है। छात्रावास के सचिव बंकट लाल वैष्णव ने सभी का धन्यवाद किया। सोबर के महासचिव इं.आर सी शर्मा, ने बताया कि आज के कार्य क्रम में जो छात्र उपस्थित नहीं थे उनको और छात्रावास के स्टाफ को भी जैकेट / कोट छात्रावास के सचिव को सुपुर्द किये गये साथ ही बताया सोबर का जरसी / जैकेट वितरण कार्य क्रम अभी जारी रहेगा।

क्रिस्मस के जश्न की शुरूआत

गीत-संगीत की धुनों पर गाया जाने लगा कैरल्स

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

माउंट आबू। क्रिसमस आने में अभी पन्द्रह दिनों का समय बाकी है लेकिन उसकी तैयारी माउंट आबू में अभी से ही शुरू हो चुकी है। बीती रात को होटल हिल लॉक सहित सोफिया स्कूल सेंट मैरीज स्कूल सेंट जोसेफ़ हायर सैकण्डरी,लुट्स विला में प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों में ईसाई समुदाय के ब्रदर्स व सिस्टर्स,व पैरिशनर्स ने मिलकर मधुर गीत-सँगीत की धुनों पर कैरल्स सिंगिंग की। साथ ही विश्वभर में सुख-शान्ति, अम्न चैन की प्रेयर्स की। फादर कॉसमॉस ने बताया कि, इस बार पैरिशनर्स सहित इंस्टीट्यूटशन से अच्छा सहयोग मिल रहा है। सभी लोग मॉस में आते है। पिछले महीने हमने मिलकर ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाया था। इस बार हम पन्द्रह दिन पहले से ही कैरल्स सिंगिंग विभिन्न स्थानो पर करते है। सेट मैरीज स्कूल व होटल हिललॉक पर इस भव्य रूप में पैरिशनर्स की ओर से एक गाँव व गौशाला की झाँकी बनायी गयी थी। जिसमे कैसे प्रभु यीशु के जन्म व मुक्ति दाता के तत्कालीन समय के स्वरूप को दर्शाया गया था। सभी स्कूल्स व इंस्टीट्यूटशन के बाद में होटल हिल लॉक में भी देर रात में मधुर संगीत की धुन पर कैरल्स सिंगिंग हुई। कार्यर् म होटल्स हिल लॉक की एम डी व समाज सेविका गीता अग्रवाल, सरिता डिसूजा जेनिफर मार्शल कैथरीन लोरीटा लिंगम सिस्टर मैरीदान सिस्टर जसरीना सिस्टर जैसविना, सिस्टर सरिता सिस्टर ग्रैजिया सहित अन्य शहरवासी उपस्थित रहे ।

आज बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक और सोशल मीडिया से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। काम आसान हुए हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ा है साइबर क्राइम। कभी फिशिंग मेल से अकाउंट खाली हो जाता है तो कभी किसी की पहचान चुराकर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दौर में साइबर इंश्योरेंस जरूरत बन गया है। यह न सिर्फ फाइनैंशल नुकसान की भरपाई करता है बल्कि मानसिक राहत भी देता है। यह क्यों ज़रूरी है, कितना मददगार है, एक्सपर्ट्स से बातकर जानकारी दे रहा है जागरूक जनता।

ठगी में ढाल बनेगा साइबर इंश्योरेंस

बढ़ते साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी और ऑनलाइन ठगी के बीच साइबर इंश्योरेंस किस तरह डिजिटल सुरक्षा कवच का काम करता है, यहां जानते हैं:

एक्सपर्ट पैनल

कर्णिका ए. सेठ साइबर लॉ एक्सपर्ट, ऐडवोकेट सुप्रीम कोर्ट

अंकित गुप्ता, हेड, रिटेल साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीबाज़ार फॉर बिज़नेस

प्रो. फरहत बी. खान डिजिटल एंड विजुअल मीडिया एक्सपर्ट

AI Image

केस से समझें

नागपुर की रहने वाली रचना (बदला हुआ नाम) हाउस वाइफ हैं। बीते दिनों उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की। पेमंट का ऑप्शन वेबसाइट पर नहीं मिला तो कस्टमर केयर पर बात की। वहां से QR कोड भेजकर पेमंट करने को कहा गया। उन्होंने 15 हजार रुपये की पेमंट कर दी। जब डिलिवरी की तारीख पर सामान नहीं आया तो उन्होंने फिर कस्टमर केयर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। बाद में उन्हें पता चला कि जिस वेबसाइट से शॉपिंग की थी, वही फेक थी। रचना को अफसोस भी हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया कि वह साइबर ठगों के जाल में कैसे फंस गई। हालांकि, इस पूरे मामले में उन्हें फाइनैंशल नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। 25 दिनों में ही उन्हें उनके 15 हजार रुपये वापस मिल गए क्योंकि उन्होंने ऐसे फ्रॉड में नुकसान से बचने के लिए पहले ही साइबर इंश्योरेंस करा रखा था।

ग्रेटर नोएडा के राजेश (बदला हुआ नाम) एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनका कंप्यूटर सिस्टम हैक हुआ और हैकर्स ने सारा सेंसिटिव डेटा हासिल कर लिया। वे राजेश को ब्लैकमेल करने लगे और उनका पूरा सिस्टम लॉक कर दिया। यह साइबर एक्सटॉर्शन का मामला था। राजेश जल्द से जल्द इस परेशानी से बाहर आना चाहते थे। उन्हें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा क्योंकि वह पहले से ही साइबर इंश्योरेंस ले चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सपर्ट्स की मदद से उनका सिस्टम अनलॉक कराया, डेटा रीस्टोर कराया और सिक्युरिटी भी मजबूत कर दी। साथ ही ब्लैकमेलिंग से पैदा हुए मानसिक तनाव को देखते हुए पॉलिसी के तहत उन्हें सायकायट्रिस्ट की मदद भी मिली। उनके लिए साइबर इंश्योरेंस वह सुरक्षा कवच साबित हुआ, जिसने मुश्किल समय में उन्हें संभाल लिया।

क्या है साइबर इंश्योरेंस

यह ऐसा इंश्योरेंस है जो साइबर हमलों, डेटा चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी ऑनलाइन ऐक्टिविटीज़ से होने वाले फाइनैंशल नुकसान और मेंटल स्ट्रेस से बचाता है। यह पॉलिसी न सिर्फ फाइनैंशल सेफ्टी देती है बल्कि साइबर फ्रॉड के बाद होने वाली जांच का खर्च और कानूनी खर्च, डेटा रिकवरी जैसी सुविधा देती है। आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल दुनिया में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग के हालात में साइबर इंश्योरेंस सहारा बनकर हर तरह के नुकसान को कम करने में मदद करता है।

क्यों है ज़रूरी

हम हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की आशंका के मद्देनज़र जैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वीइकल इंश्योरेंस तो सभी ज़रूर कराते हैं, उसी तरह डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए साइबर इंश्योरेंस ज़रूरी हो गया है। जिस तरह कोई बीमारी हमें बताकर नहीं आती, ठीक वैसे ही हम नहीं जानते कि कब किस साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएं। अगर हमारे बैंक अकाउंट से धोखे से पैसे निकल जाएं, मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाए, पर्सनल जानकारी लीक कर दी जाए या कोई ऑनलाइन ब्लैकमेल करे तो साइबर इंश्योरेंस इन हालात में होने वाले नुकसान की भरपाई करता है।

इन सभी हालात में संभालता है इंश्योरेंस

अकाउंट में ठगी से लेकर पहचान की चोरी तक... ये सब हैं कवर

डिजिटल थेफ्ट ऑफ फंड्स

फिशिंग, स्पूफिंग और हैकिंग जैसे साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। फिशिंग में ठग किसी बैंक, कंपनी या सरकारी एजेंसी के नाम से फर्जी ईमेल या SMS भेजकर OTP, पासवर्ड, बैंक डिटेल या कार्ड की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। वहीं, स्पूफिंग में ठग अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे की पहचान से ज़रूरी जानकारियां हासिल कर ठगी करते हैं या फिर सिस्टम ही हैक कर लेते हैं। ऐसे हालात में अकाउंट से पैसे निकल जाने से फाइनैंशल नुकसान होता है।

यह मिलती है मदद: पॉलिसी में जितने अमाउंट का कवर लिया होता है उतने रुपये वापस मिल जाते हैं। मान लें, 5 लाख रुपये का कवर प्लान में ले रखा है तो इतने अमाउंट तक की ठगी होने पर वे रुपये वापस मिलते हैं।

आइडेंटिटी थेफ्ट

आजकल साइबर ठग केवल बैंक अकाउंट को ही नहीं बल्कि हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी को भी निशाना बनाते हैं। वे हमारी पर्सनल जानकारी जैसे आधार नंबर, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, बैंक डिटेल या यहां तक कि सोशल मीडिया प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन जानकारियों की मदद से वे फर्जी खाते खोल सकते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं।

यह मिलती है मदद: पॉलिसी के तहत क्रेडिट मॉनिटरिंग, आइडेंटिटी मॉनिटरिंग, डेटा रिकवरी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई से जुड़ा खर्च भी मिलता है। अगर आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से जॉब या काम पर असर पड़ा है और सैलरी का नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई भी पॉलिसी के कवर लिमिट के अनुसार मिल सकती है।

मॉलवेयर/डेटा ब्रीच

कई बार मोबाइल, लैपटॉप या किसी और डिवाइस में मालवेयर घुस जाता है या अचानक डेटा चोरी हो जाता है। ऐसे मामलों में न सिर्फ सिस्टम खराब होता है बल्कि ज़रूरी फाइलें भी खराब हो जाती हैं।

यह मिलती है मदद: साइबर इंश्योरेंस तकनीकी मदद का खर्च कवर करता है। पॉलिसी के तहत IT एक्सपर्ट की मदद से डेटा रिकवरी कराई जाती है और डिवाइस को साइबर घटना से पहले वाली स्थिति के जितना करीब हो सके, उतना ठीक कराया जाता है। इसमें डिवाइस की मालवेयर हटाने, सिस्टम की मरम्मत और सुरक्षा मजबूत करने जैसे ज़रूरी खर्च शामिल होते हैं। इससे जल्द अपने काम पर लौट पाते हैं और डेटा नुकसान से बच जाते हैं।

गलती से दूसरे को नुकसान

कभी-कभी साइबर घटना का असर सिर्फ हमारे सिस्टम पर नहीं बल्कि किसी दूसरे के सिस्टम पर भी पड़ सकता है। मान लें, हमारे मोबाइल या लैपटॉप में वायरस है या उसमें सिक्युरिटी की कमी है। हम उससे कोई ईमेल या कोई फाइल किसी को भेजते हैं और इस वजह से दूसरे शख्स के कंप्यूटर, मोबाइल को नुकसान हो जाता है, जैसे उनका डेटा डिलीट हो जाए, चोरी हो जाए या सिस्टम ठप हो जाए। ऐसे में दूसरा शख्स कह सकता है कि हमारी लापरवाही से उसे नुकसान हुआ है।

यह मिलती है मदद: अगर हमारी चूक से तीसरे शख्स (थर्ड पार्टी) को साइबर नुकसान हुआ हो तो पॉलिसी उसकी भरपाई करती है। अगर वह शख्स हम पर कानूनी कार्रवाई करे तो वकील की फीस, कानूनी खर्च आदि भी कवर होता है।

ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड

ऑनलाइन खरीदारी करते समय कई बार ठग नकली वेबसाइट, फर्जी ऑफर या गलत पेमंट लिंक देकर फंसाते हैं। वे पेमंट तो करवा लेते हैं, लेकिन न सामान भेजते हैं और न कोई सर्विस देते हैं। जब कस्टमर सर्विस एजेंट को कॉल करते हैं तो वेबसाइट के फेक होने और साइबर फ्रॉड होने का पता चलता है। ऐसी स्थिति में परेशान होने या पुलिस में शिकायत करने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते।

यह मिलती है मदद: साइबर इंश्योरेंस ऐसे मामलों में हुए सीधे फाइनैंशल नुकसान को कवर करता है। शर्त यह होती है कि ठग या बेचने वाले से रिफंड पाने की कोशिश की गई हो और घटना की जानकारी अपने बैंक, कार्ड जारीकर्ता या संबंधित संस्था को 48 घंटे के अंदर दी हो। अगर ये जरूरी कदम उठा लें तो डिलिवर नहीं हुए सामान या फर्जी ट्रांजेक्शन से हुए नुकसान की भरपाई पॉलिसी के तहत हो जाती है।

स्मार्ट होम कवर

आजकल कई घरों में स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाते हैं, जैसे स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम और दूसरे इंटरनेट-कनेक्टेड कंट्रोल डिवाइस। मालवेयर अटैक या साइबर घटना की वजह से ये पूरे सिस्टम खराब हो सकते हैं।

यह मिलती है मदद: साइबर इंश्योरेंस ऐसे मामलों में स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम को ठीक करने और पहले की स्थिति में वापस आने का खर्च कवर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मालवेयर की वजह से स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हो जाए तो उसकी मरम्मत और रिस्टोरेशन का खर्च पॉलिसी अपने दायरे में लेती है। इससे घर के ऑटोमेशन और सेफ्टी से जुड़ी सुविधाएं बिना एक्स्ट्रा खर्च के दोबारा सुचारू रूप से चलने लगती हैं।

साइबर एक्सटॉर्शन

कई बार हैकर्स कंप्यूटर, मोबाइल या पूरे सिस्टम को लॉक कर देते हैं और बदले में पैसे यानी फिरौती (Ransom) मांगते हैं। इसे साइबर एक्सटॉर्शन कहा जाता है। इसमें अपराधी सेंसिटिव डेटा को लीक करने, डिलीट करने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं।

यह मिलती है मदद: इंश्योरेंस में सिस्टम अनलॉक कराने, डेटा रिकवर करने और साइबर एक्सटॉर्शन को सुलझाने में आने वाले ज़रूरी खर्च को कवर किया जाता है। साथ ही, जहां कानून इजाजत देता हो वहां पैसों के भुगतान की राशि भी कवर लिमिट के अंदर शामिल हो सकती है। इससे बड़े नुकसान से बचने के साथ ही समस्या जल्दी हल हो जाती है।

साइबर बुलिंग

कई बार साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे या परिवार मानसिक तनाव में आ जाते हैं। लगातार ऑनलाइन धमकियां, परेशान करने वाले संदेश, बदनाम करने वाली पोस्ट सेफ्टी और मेंटल हेल्थ पर असर डालती हैं। कई मामलों में तो बच्चे को सुरक्षित माहौल देने के लिए स्कूल या कॉलेज बदलना या किसी दूसरी जगह घर शिफ्ट करना पड़ता है।

यह मिलती है मदद: अगर किसी एक्सपर्ट या संबंधित अथॉरिटी ने सलाह दी हो कि साइबर बुलिंग की वजह से स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बदलना ज़रूरी है तो इसका खर्च, फीस आदि पॉलिसी के तहत कवर हो सकता है।

इन हालात में कवर नहीं

पहले से पता होने वाली घटनाएं: अगर पॉलिसी शुरू होने से पहले ही किसी साइबर समस्या के बारे में पता हो, जैसे कि सिस्टम में पहले से वायरस हो, कोई संदिग्ध ऐक्टिविटी दिखे या हैकिंग का खतरा लगे।

जानबूझकर की गई गलती: अगर साइबर घटना जानबूझकर की गई गलती, लापरवाही, बुरी नीयत, धोखाधड़ी या गलत बर्ताव की वजह से हुई हो।

बिज़नेस से जुड़ीं ऐक्टिविटीज़: अगर साइबर घटना ऑफिस के काम, नौकरी, प्रफेशनल काम या किसी बिज़नेस ऐक्टिविटी के दौरान हुई हो। यह पॉलिसी केवल पर्सनल इस्तेमाल के लिए है।

फिजिकल डैमेज: अगर किसी साइबर घटना में कोई सामान (जैसे डिवाइस, मशीन, उपकरण आदि) टूट जाए, खराब हो जाए या वह काम करना बंद कर दे।

ट्रेडिंग या निवेश का नुकसान: शेयर, क्रिप्टो या किसी भी तरह के निवेश और ट्रेडिंग में होने वाला नुकसान।

क्रिप्टोकरेंसी का नुकसान: क्रिप्टोकरेंसी (जैसे Bitcoin, Ethereum आदि) खो जाना, चोरी हो जाना, डिलीट होना, लॉक हो जाना, उसकी ट्रेडिंग में देरी होना या कीज़ का गुम हो जाना।

इंश्योर्ड के बीच किए गए क्लेम: अगर बीमा पॉलिसी में शामिल दो लोग आपस में ही एक-दूसरे पर दावा करें। (थर्ड पार्टी क्लेम स्वीकार नहीं होते)।

ज्यादा जिम्मेदारी: किसी कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदारी ले ली और उससे नुकसान हुआ है।

युद्ध जैसे हालात: हमला, सैन्य कार्रवाई या किसी भी तरह की ऐसी घटना से हुआ नुकसान।

साथ ही जुआ या सट्टेबाजी में होने वाला कोई नुकसान।

ये कंपनियां दे रहीं साइबर इंश्योरेंस

SBI General Insurance, Shriram General Insurance, Zurich Kotak General Insurance, HDFC ERGO General Insurance, Tata AIG General Insurance, ICICI Lombard General Insurance

नोट: इनके अलावा और भी कंपनियां साइबर धोखाधड़ी में नुकसान को कवर करने के लिए पॉलिसी देती हैं।

दो तरह के हैं प्लान

साइबर इंश्योरेंस में दो तरह के प्लान आते हैं। पहला पर्सनल और दूसरा बिज़नेस। पर्सनल प्लान में कोई शख्स सिर्फ खुद को या फैमिली को कवर कर सकता है जबकि बिज़नेस प्लान बड़ी कंपनियों के लिए होता है, जिन्हें इस तरह के साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक का खतरा होता है।

पर्सनल प्लान को समझें

1. **इंडिविजुअल प्लान:** इसमें कोई शख्स सिर्फ खुद को साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक से कवर करता है।
2. **फैमिली प्लान:** इसमें कोई शख्स खुद को और अपनी फैमिली को भी ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए पॉलिसी लेता है। ध्यान रखें कि फैमिली प्लान में 2 अडल्ट यानी 18+ और 2 माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के कुल 4 लोग ही कवर हो सकते हैं। कोई शख्स खुद को, पत्नी को और दो बच्चों को इसमें कवर कर सकता है, पैरंट्स को नहीं। पैरंट्स के लिए अलग-से पॉलिसी लेनी होगी।

किस तरह से चुनें प्लान

प्लान का चुनाव करते समय अपनी ज़रूरतों को देखें। अगर सामान्य साइबर फ्रॉड जैसे डिजिटल थेफ्ट ऑफ फंड्स और आइडेंटिटी थेफ्ट का डर है तो बेसिक प्लान से ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई साइबर एक्सटॉर्शन या साइबर बुलिंग कर सकता है तो इन चीजों को पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। किस कंपनी का प्लान लेना है, इसके लिए अलग-अलग कंपनियों की वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। अगर कई कंपनियों के प्लान एक जगह देखने हैं तो smebusiness.policybazaar.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहां Personal Cyber Security Insurance का ऑप्शन दिखेगा। अपना नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद सभी कंपनियों के प्लान एक साथ देख सकते हैं। उनके रेट की तुलना, सुविधाओं की जानकारी आदि सब जान सकते हैं।

जितना खर्च, उतना कवर

साइबर इंश्योरेंस की शुरुआत 199 रुपये सालाना से होती है, जिसमें 10 हजार रुपये तक के फ्रॉड से कवर मिलता है। अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग रेट पर कवर देती हैं। इसमें हम 10 हजार रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के फ्रॉड से बचने के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। जानते हैं इंडिविजुअल प्लान में कितने खर्च में कितना कवर होता है:

खर्च (रु.)	कवर (रु.)
199 से	10 हजार
203 से	25 हजार
243 से	50 हजार
325 से	1 लाख
351 से	2 लाख
389 से	3 लाख
446 से	5 लाख
625 से	10 लाख
874 से	20 लाख
1363 से	50 लाख
2994 से	1 करोड़

(नोट: यहां किसी कंपनी की ओर से दी जाने वाली सबसे किफायती पॉलिसी के आधार पर सालाना खर्च दिया गया है। अलग-अलग कंपनियों का पॉलिसी रेट उनकी ओर से दी जानी वाली सुविधाओं के आधार पर अलग-अलग होता है।)

लेने होते हैं Add-ons: यहां पॉलिसी के बेसिक प्लान का रेट बताया गया है यानी इसमें केवल शुरुआती चीजें जैसे डिजिटल थेफ्ट ऑफ फंड्स और आइडेंटिटी थेफ्ट ही कवर होते हैं। दूसरी चीजें कवर करने के लिए Add-ons लेने होते हैं।

उदाहरण से समझें: अगर थेफ्ट ऑफ फंड्स और आइडेंटिटी थेफ्ट के साथ साइबर एक्सटॉर्शन शामिल करते हैं तो पॉलिसी का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। खर्च अलग-अलग कंपनियों के अनुसार अलग होता है।

दिल्ली से मोदी-पूतिन का दुनिया को संदेश, कहा- आतंक से लड़ाई में भारत-रूस एक

यूक्रेन मसले पर न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ हैं: PM

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली: भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पूतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया-रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि शांति कायम करने की कोशिशों का भारत समर्थन करता रहा है। हम अपना योगदान देते रहे हैं और देते रहेंगे। उन्होंने कहा, हमने हमेशा दुनिया के नेताओं से कहा कि भारत इस मसले में न्यूट्रल नहीं है। भारत का पक्ष है और वह है- शांति का पक्ष। हम शांति के सारे प्रयासों का समर्थन करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूतिन ने भी मोदी के साथ लगातार संपर्क में रहने और संवाद करते रहने का जिक्र किया। पीएम ने कहा पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं, विश्वास है कि विश्व शांति की दिशा में लौटेगा। इस बीच, उन्होंने भारत-रूस संबंधों को मजबूत करने में पूतिन की अटूट प्रतिबद्धता की भी सराहना की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम में आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस दोनों एकजुट हैं।

- **मोदी बोले, हमने हमेशा दुनिया के नेताओं से कहा कि भारत का पक्ष शांति का पक्ष है।**
- **रूसी राष्ट्रपति पूतिन ने कहा, भारत के लिए बिना रुकावट के जारी रहेगा रूसी तेल का शिपमेंट**

इस दौरान, पूतिन ने कहा कि हमने सुरक्षा, इकॉनमी, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं पर सहमति बना ली है। पूतिन ने द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब डॉलर तक बढ़ने की बढ़ने की उम्मीद जताई। पूतिन ने आगे कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली के लिए अपनी राष्ट्रीय करंसी के इस्तेमाल की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पूतिन ने आगे कहा कि रूस, भारत के लिए गैस और तेल का विश्वसनीय सप्लायर रहा है। पूतिन ने कहा कि भारत के लिए बिना रुकावट तेल का शिपमेंट जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हम बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं।

रूस को गिफ्ट, 30 दिनों के लिए फ्री e-टूरिस्ट वीज़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत-रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के बीच संबंधों ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों में एक खास जगह रखी है और नई दिल्ली जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत-रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के संबंधों का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक-दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान, और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिनों के ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनशक्ति गतिशीलता हमारे लोगों को जोड़ने के साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए मौके लाएगी।

पीएम ने पूतिन को दिए खास तोहफे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें भारत की विविध संस्कृति को दर्शाने वाले कई खास तोहफे दिए। इन तोहफों में आगरा का बारीक कारीगरी वाला मार्बल शतरंज सेट, असम की मशहूर ब्लैक टी, कश्मीर का खुशबूदार केसर और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) का खूबसूरत चांदी का टी-सेट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की दस्तकारी वाला चांदी का घोड़ा भी भेंट में दिया गया। सबसे खास तोहफा था रूसी भाषा में अनुवादित श्रीमद् भगवद् गीता, जिसे पीएम मोदी ने पुतिन को सौंपा। ये तोहफे भारत की कला, परंपरा और दोस्ती की गर्मजोशी को दिखाते हैं।

पूतिन ने राजघाट पर गांधी को श्रद्धांजलि दी

कहा- महात्मा गांधी ने दुनिया में शांति के लिए अमूल्य योगदान दिया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने शुक्रवार को राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूतिन ने एक विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किया, जिस पर एक संदेश लिखा था। महात्मा गांधी के लिए दिए संदेश में पुतिन ने लिखा कि आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक के रूप में उन्होंने विश्व शांति के लिए अमूल्य योगदान दिया।

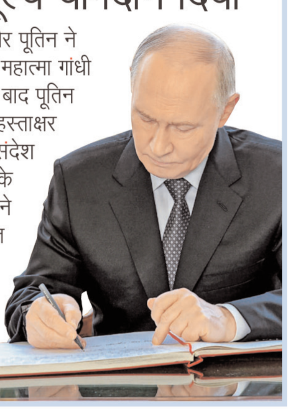

16 करार, कई ऐलान... क्या कुछ निकला पूतिन के भारत दौरे से

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली: राष्ट्रपति पूतिन के 27 घंटे के भारत दौरे में दोनों देशों ने रिश्तों को मजबूत करने के लिए 16 बड़े करार (MoU) पर हस्ताक्षर किए। माइग्रेशन, शिक्षा, मीडिया, शिपिंग, हेल्थकेयर से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा तक, कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बातचीत का मुख्य फोकस था- आर्थिक संबंधों को बढ़ाना और व्यापार असंतुलन को कम करना।

आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सहमति: भारत और रूस ने माना कि व्यापार बढ़ाने के लिए टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटें कम करनी होंगी। दोनों देशों ने कहा कि राष्ट्रीय करेंसी में व्यापार जारी रखने से लेनदेन आसान होगा। क्रिटिकल मिनरल्स और कीमती धातुओं पर रिसर्च और निवेश को भी प्राथमिकता दी गई। लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच सके।

साझा बयान में आतंक से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग की बात

आतंकवाद पर कड़ा रुख: साझा बयान में सीमापार आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया गया। दोनों देशों ने पहलगाम आतंकी हमले और रूस के क्रोकस सिटी हॉल हमले का जिक्र करते हुए अल-कायदा, ISIS जैसे संगठनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। एक सवाल के जवाब में मिस्री ने बताया कि आतंकवाद के मामले पर दोनों देशों के बीच खुलकर बातचीत हुई। रूस की ओर से हमेशा इस मुद्दे पर सहानुभूति, सहारा और समर्थन मिला है। हमें उम्मीद है कि आगे भी ये जारी रहेगा।

ऊर्जा और परमाणु सहयोग: दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गहरी चर्चा की। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुदनकुलम प्लांट की बची इकाइयों की टाइमलाइन पर जोर दिया गया और एक नई साइट पर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति हुई।

स्पेस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग

रॉकेट इंजन के उत्पादन और उपयोग में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने माना कि स्पेस टेक्नॉलजी में साझेदारी आगे भी जारी रहेगी।

माइग्रेशन, शिपिंग और हेल्थकेयर के करार

- माइग्रेशन और मोबिलिटी पर दो अहम करार हुए। एक अस्थायी श्रमिक गतिविधि पर, दूसरा अनियमित माइग्रेशन रोकने के लिए।
- हेल्थकेयर, मेडिकल शिक्षा और फूड सेफ्टी पर समझौते हुए।
- शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट से जुड़े दो करार भी साइन किए गए।
- फर्टिलाइजर, कस्टम और कॉमर्स से जुड़े करारों को मंजूरी मिली।
- शिक्षा और मीडिया सहयोग को लेकर कई समझौते हुए, जिनमें पुणे के डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ अड्वांस्ड टेक्नॉलजी (DIAT) और रूस की नैशनल टोम्स्क यूनिवर्सिटी का करार प्रमुख है।
- प्रसार भारती और रूसी मीडिया के बीच 5 समझौते हुए।

2030 तक रणनीतिक सहयोग का रोडमैप

भारत और रूस ने मिलकर 2030 तक रणनीतिक आर्थिक क्षेत्रों के विकास का रोडमैप तय करने की घोषणा की। रूस ने इंटरनैशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क को अपनाने का भी फैसला किया।

रूस की कंपनियों को पीएम का न्योता-आइए, भारत में बनाइए

भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए मोदी ने रूसी कंपनियों को न्यौता देते हुए कहा-आइए और भारत मे बनाइए.... भारत के साथ साझेदारी कीजिए। पीएम ने कहा किदोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के जल्द समापन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। भारत-रूस आईएनएसटीसी, नॉर्दन सी रूट, चेन्नै व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर के मामले पर नई ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे। दोनों देश प्रशिक्षण और कौशल पर भी काम करेंगे। छात्रों, स्कॉलर्स और खिलाडियों का आदान प्रदान भी बढ़ाया जाएगा।

देश के जॉंबाज एवं अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित सिपाही और ख्यातीनाम अन्तराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय में सम्मानित

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संघटक राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर एवं पूर्व छात्र परिषद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं की भूमिका'' विशयक व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का सफल आयोजन महाविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में किया गया ।

समारोह का शुभारम्भ करते हुये राजस्थान कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं पूर्व छात्र परिषद् के मुख्य संरक्षक डॉ मनोज महला ने कहा कि यह मंच देश के जॉबाज सिपाही और ख्यातीनाम अन्तराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक का स्वागत एवं सम्मान करते हुये गौरवान्वित महसुस कर रहा है जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र योगेन्द्र सिंहजी राठौड़ पधारे हैं जिन्होने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में देश की और राजस्थान प्रदेश की 500 किलोमीटर लम्बी अन्तराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का भार बखुबी अपने कन्धों पर उठा रखा था, जिसके उपलक्ष्य में आपको अति उत्कृश्ट सेवा मेडल तथा पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया गया है। यही नहीं राठौड़ ने कारगिल युद्ध के दौरान आपरेशन विजय में उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर विजय मेडल प्राप्त किया। राठौड़ ने चार बार पूरे देश की सीमा सुरक्षा बल दिवस परेड़ का नेतृत्व कर रखा है। आपने यूनाईटेड नेशन में रहते हुये कोसोवा, युगोस्लाविया में अपनी सेवा से यूएन मेडल भी प्राप्त किया है। पर्यावरण के प्रति सजगता से सेवा कर आपने वृक्ष मित्र एवार्ड 2023 भी जीत रखा है। ऐसे जॉबाज और दिलेर सिपाही को अपने बीच में पाकर आज हमारे विद्यार्थी अपने आपको भाग्यशाली समझेगें और आपश्री का अनुकरण करेगें। इसी अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व छात्र मेवाड़ की मिट्टी के सपूत अन्तराष्ट्रीय ख्यातीनाम कृशि वैज्ञानिक डॉ लाल सिंह सारगंदेवोत जो कि वर्तमान में अमेरिका के प्रसिद्ध कैलिफ़ोर्निया स्टैट युनिवर्सिटी में एमरेटस प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाऐं दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हुये डॉ महला ने कहा कि आज महाविद्यालय परिवार उत्साहित एवं प्रफुलित हैं।

श्री अन्नमक्का में MSP और मंडी भाव में भारी अंतर-चौधरी

चित्तौड़गढ़ @ जागरूक जनता। किसान नेता राहुल चौधरी चिकसी ने श्री अन्न-मक्का उत्पादक किसानों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों ने सरकार की अपील पर बड़े पैमाने पर मक्का बुवाई की, लेकिन फसल आते ही उन्हें गहरा आर्थिक झटका लगा है। सरकार ने मक्का का MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि जिले की मंडियों में भाव 1300-1500 रुपये ही मिल रहा है। चौधरी ने सवाल किया कि "मेहनत और जोखिम उठाने वाले किसान को उसकी फसल का सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा?" उन्होंने बताया कि किसान YHI हाइब्रिड बीज 25,000-30,000 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदता है, लेकिन तैयार मक्का मात्र 1300-1500 रुपये में बेचने को मजबूर है। चौधरी ने कहा कि मौसम, कीट दबाव और बढ़ती लागत के बावजूद किसान फसल तैयार करता है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्रों के नहीं खुलने और मंडियों में मनमाने भाव के चलते उसकी मेहनत घाटे में बदल जाती है।

घर मंगवाये जागरूक जनता

सदस्यता फार्म दिनांक ....

जागरूक जनता हिन्दी अखबार एक उद्देश्य, एक मिशन, एक विश्वास के साथ आमजन की समस्याएं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक गलियारा, भौगोलिक दृष्टिकोण को एक-दूसरे से साझा करने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं तकनीकी जानकारी पहुंचाकर शहरी एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। जागरूक जनता समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों के साथ- अपने पाठकों के बीच उपस्थित रहता है।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 250/- ☐ दो वर्ष रु. 450/- ☐ तीन वर्ष रु. 600/- ☐ पांच वर्ष रु. 1000/-

डाक से नियमित रुप से निम्न पते पर जागरूक जनता भेजने के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर जागरूक जनता के नाम भेज रहा हूं। फोन-पे, पेटीएम-9829329070

नाम / संस्था का नाम ....

पता : ....

....

फोन .... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

राशि (रुपए) .... बैंक का नाम ....

डिमान्ड ड्राफ्ट / मनीऑर्डर क्रमांक ☐☐☐☐☐☐ (डीडी/एमओ जागरूक जनता के नाम भेजें)

- सदस्यता रजिस्ट्रेशन क्रं. ....रसीद क्रं. ....

दिनांक .... हस्ताक्षर

सदस्यता हेतु लिखे प्रसार प्रभारी →

जागरूक जनता
सकारात्मक हिन्दी अखबार

बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.) मो.- 9829329070, 9928022718

निट्रा और रूमा देवी फाउंडेशन के बीच एमओयू : जैकेट, दस्ताने, कपड़ों समेत दर्जनों उत्पाद बन रहे

'आक' बनेगा कमाई का जरिया-रूमा देवी

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

बाड़मेर @ डालू राम। राजस्थान की मरुधरा में उगने वाले 'आक' के पौधे अब केवल रेगिस्तानी वनस्पति नहीं रहे, बल्कि ग्रामीण रोजगार और सस्टेनेबल फैशन की नई क्रांति का आधार बन रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय के उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा आक के पौधे जिन्हें एक खरपतवार की तरह देखा जाता आ रहा है, उसके रेशों से सर्दीयों के कपडे, दस्ताने व जुराब समेत बर्फिले ईलाकों के लिए टेन्ट भी बनाए जा रहे हैं।

नवंबर 2025 में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के निट्रा में आक की फसलों का निरक्षण करने के बाद इस परियोजना को तेजी मिली, इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वस्त्र मंत्रालय से संबद्ध उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संस्थान निट्रा के महानिदेशक एम एस परमार तथा रूमा देवी फाउंडेशन की निदेशक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर व

समाज सेविका डॉ. रूमा देवी ने गाजियाबाद स्थित वस्त्र अनुसंधान केंद्र में एक एम ओ यु पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बहुतायत में पाए जाने वाले 'आक' के फल 'आक-पाडिया' से उच्च गुणवत्ता वाला रेशा तैयार कर आक की खेती पर अनुसंधान व तकनीकी विकास के साथ साथ देश विदेश में आक से बने उत्पादों को प्रचलित करना है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।

क्या है आक में ऐसे खास

अब तक बेकार समझे जाने वाले आक के फल से निकलने वाला रेशा ऊन से भी ज्यादा गर्म और रेशम जैसा मुलायम होता है। आक के तने से भी रेशा निकला जाता है व फल की खाल भी काफ़ी उपयोगी होती है, साथ ही आक में काफ़ी औषधीय गुण भी होते है। आक के बीज से तेल निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल फेसियल क्रीम बनाने में किया जाता है। आक का पौधा कम पानी व विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहता है व एक एकड़ में 200 से 300 किलो तक फसल का उत्पादन किया जा सकता है। आक से बने रेशो की माँग इसकी आपूर्ति से कहीं अधिक है। वस्त्र मंत्रालय की सहायता से निट्रा के महानिदेशक एम एस परमार अपनी आधुनिक प्रयोगशालाओं में इस रेशे की गुणवत्ता, मजबूती और इससे कपड़े बनाने की तकनीकी प्रक्रिया पर काम कर रहे है। फाउंडेशन की निदेशक डॉ रुमा देवी ने बताया कि आक के पौधे के औषधीय व धार्मिक महत्व के पश्चात अब आक के पौधे की इतनी व्यवसायिक उपयोगिता देख कर बहुत खुशी हुई, चूंकि आक के पौधे क्षेत्र में बहुतायत में उपलब्ध हैं, आक की खेती किसानों के लिए रोजगार का बहुत अच्छा साधन बनेगी। आक के रेशे से जैकेट, दस्ताने, कंबल और कपड़ों समेत दर्जनों उत्पाद बन रहे हैं। अब इसे विश्व व्यापी पहचान दिलाई जाएगी।

प्रारंभिक चरण में 2000 किलो आक का रेशा सफलतापूर्वक हुआ एकत्रित

पिछली गर्मीयो में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर रूमादेवीफाउंडेशन ने बाड़मेर जोधपुर जैसलमेर बिकानेर व नागौर से 2000 किलो आक पाडीए एकत्रित करने का बीड़ा उठाया। इस पहल से किसान परिवारो को बिना लागत के खेतो में अपने आप उगे आक से पोड इकट्ठे कर घर से ही रोजगार मिलने लग गया। प्रारंभिक चरण की सफलता के बाद अब इसकी जागरूकता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। रूमा देवी ने बताया कि होली के आसपास आक पर रेशा पककर तैयार होने लगता है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाएगें।

एम ओ यू हस्ताक्षर समारोह में डॉ. एमएस परमार महानिदेशक, निट्रा, डॉ रूमा देवी, निदेशक रूमा देवी फाउंडेशन के साथ रूमा देवी फाउंडेशन की और से विक्रम सिंह, प्रवक्ता हर्षिता सिंह व निट्रा की और से डॉ प्रीति व टीम उपस्थित रही।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक ज्ञानेन्द्र मिश्रा के लिए जैमन प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी-1-68, रोड नम्बर-14, वीकेआई, जयपुर से मुद्रित एवं प्रशासनिक और विज्ञापन कार्यालय : बी-132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर-302039 से प्रकाशित। फोन : 0141-3587886

संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दिया नया टास्क

अब पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' फेज में है देश-मोदी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दलों की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश अब पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' फेज में है। जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे के साथ हो रहे हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को जनता के बीच जाने को कहा है। साथ ही अगला टार्गेट बंगाल चुनाव है।

सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू पर फोकस हैं। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की रुकावटों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।

रिफॉर्म एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके

पीएम ने एनडीए सांसदों से आम लोगों की असली समस्याओं को सरि य रूप से शेयर करने का आग्रह किया है ताकि रिफॉर्म एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके और रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर कर सकें।

गैर जरूरी कागजात के कल्चर को करना है खत्म

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वह 30-40 पेज के फॉर्म और गैर जरूरी कागजात के कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि हमें नागरिकों के दरवाजे पर सेवाएं देनी हैं। बार-बार डेटा जमा करने की प्रक्रिया को खत्म करना है।

ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टॉप प्रॉयोरिटी

एनडीए संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने याद दिलाया कि सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन की अनुमति देकर नागरिकों पर भरोसा किया है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह भरोसा 10 सालों से बिना किसी गलत इस्तेमाल के सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों मोदी सरकार की टॉप प्रॉयोरिटी हैं।

सांसदों को पीएम मोदी ने दिया ये टास्क

पीएम मोदी ने सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय रहने और जनता से जुड़ने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की शानदार जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल चुनाव अगला बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा, उन्होंने सांसदों से आगामी बजट पर फीडबैक देने, स्थानीय कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा कृषि राहत पैकेज, लेकिन

भारत के चावल आयात को 'टैरिफ की धमकी'

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों के लिए कई अरब डॉलर की राहत योजना का ऐलान किया और भारत सहित एशियाई देशों से आने वाली कृषि आयात पर अपनी नाराजगी भी जताई। व्हाइट हाउस में किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिकी किसानों की सुरक्षा के लिए शुल्क (टैरिफ) का कड़ा इस्तेमाल किया जाएगा।

ट्रंप ने शुल्क लगाने को कृषि क्षेत्र को संभालने की उनकी योजना का अहम हिस्सा बताया

ट्रंप ने बताया कि सरकार किसानों को लगभग 12 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देगी, जिसे अमेरिका ट्रेडिंग पार्टनर्स से मिल रहे टैरिफ रेवेन्यू से फंड करेगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों की महंगाई और कमजोर दामों से किसान परेशान हैं, इसलिए यह मदद जरूरी है। ट्रंप ने किसानों को अमेरिका की रीढ़ बताते हुए कहा कि शुल्क लगाना कृषि क्षेत्र को संभालने की उनकी योजना का अहम हिस्सा है।

भारत का जिक्र खास तौर पर चावल आयात के मुद्दे पर आया

दरअसल, बैठक में भारत का जिक्र खास तौर पर चावल आयात के मुद्दे पर आया। लुइज़ियाना की एक चावल उत्पादक कंपनी की सीईओ मेरिल कैनेडी ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देश बहुत सस्ता चावल भेज रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसान मुश्किल में हैं। उन्होंने ट्रंप से कहा कि शुल्क बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ केस का ज़िक्र करते हुए कड़ी पाबंदियां लगाने की अपील की। ट्रंप को जब बताया गया कि अमेरिका में बिकने वाले दो बड़े चावल ब्रांड भारतीय कंपनियों के हैं, तो ट्रंप ने कहा कि वह तुरंत कार्रवाई करेंगे और टैरिफ लगाने से समस्या कुछ ही मिनट में हल हो जाएगी। बैठक में सोयाबीन और अन्य फसलों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है और चीन भारी मात्रा में अमेरिकी सोयाबीन खरीद रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चीन आने वाले समय में बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने का वादा कर चुका है।

राष्ट्रगीत पर संसद में बहस पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा तो गीत के टुकड़े हुए।

कांग्रेस ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए: PM

तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस को देश के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। -नरेन्द्र मोदी, पीएम

चर्चा असली सवालों बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक, प्रदूषण से ध्यान भटकाने को जानबूझकर कराई गई है। -प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद

मोदी ने नेहरू पर साधा निशाना

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

पीएम नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सोमवार को देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, 'जब मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने वंदे मातरम् का विरोध किया तो नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र में लिखा कि मैंने वंदे मातरम् का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। इस दबाव में कांग्रेस झुक गई और वंदे मातरम् के टुकड़े कर दिए, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और वंदे मातरम के जब 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए, तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया।'

गीत के 100 साल होने पर इमरजेंसी में जकड़े थे: मोदी

मंशा पर सवाल उठा विपक्ष ने बीजेपी को घेरा

जरूरी सवालों से ध्यान भटकाने वाली बहस बताते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने कहा, पीएम अच्छा भाषण देते हैं, मगर तथ्यों में कमजोर हैं। नेहरू की लिखी चिट्ठी को आधा-अधूरा पढ़ा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में कहा कि वंदे मातरम् का नारा ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में लगाया जाता था। बीजेपी के राजनीतिक पूर्वजों ने इस मंशा को कब पूरा किया?

पुलिस लेगी इंटरपोल की मदद

गोवा की रोमियो लेन के आरोपी इंडिगो की फ्लाइट से फरार

PTI

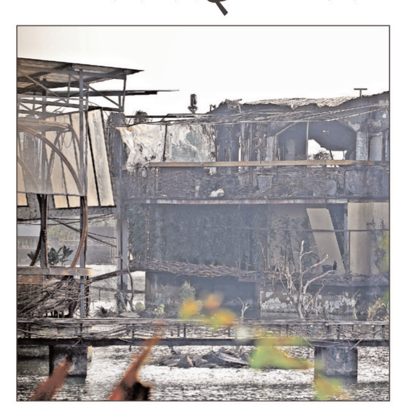

पीड़ित की अंतिम विदाई... नाइटक्लब में लगी आग में मारे गए मोहित मुंडा का सोमवार को झारखंड के खूंटी जिले में अंतिम संस्कार किया गया।

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

भले ही पूरा देश इंडिगो की फ्लाइट कैंसल होने से परेशान है, लेकिन संयोग देखिए कि गोवा के क्लब में आग लगने से जहां 25 लोग मारे गए, उस क्लब के आरोपी मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की ही उड़ान से थाइलैंड के फुकेत (Phuket) को भाग गए। हैरानी की बात है कि ये फ्लाइट कैंसल नहीं हुई। गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा दोनों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए CBI के इंटरपोल डिविजन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और कदम उठाए हैं।

मामले में गोवा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली में क्लब के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारी की पहचान सब्जी मंडी निवासी भरत कोहली के रूप में हुई है। वह क्लब के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभालता था और एक प्रबंधक से हुई पूछताछ में उसका नाम सामने आया। कोहली को अब आगे की पूछताछ के लिए गोवा ले जाया जाएगा। गोवा पुलिस की टीम क्लब मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा के घर भी पहुंची। दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने एक पोस्ट लिखकर जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था। ▶▶पेज 11

राज्य सरकार ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई

25 लोगों की मौत के बाद 'रोमियो लेन' कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। गोवा में इस कंपनी की दो अन्य संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है। -गोवा सरकार

IPS अधिकारियों पर भी लगे आरोप

Murari.Shetye@timesofindia.com

पणजी: मामले की जांच में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर स्थानीय पुलिस की कार्रवाई रोकने का आरोप लगा है। आरोप है कि अंजुना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने क्लब मालिक से परमिशन और दस्तावेज मांगे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने नोटिस आगे बढ़ाने और एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोका। आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव और पिछले साल अगस्त में भी क्लब को लेकर नोटिस और एफआईआर दर्ज करने की कोशिशें रोक दी गईं। जांच में शामिल अधिकारी का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड जांचने पर अधिकारियों और क्लब मालिकों के संबंध सामने आ सकते हैं।

फटाफट खबरें

मुनाफावसूली से शेयर बाज़ार लुढ़का

सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट हुई। सेंसेक्स 609.68 अंक गिरकर 85,102.69 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 225.90 अंक लुढ़ककर 25,960.55 अंक पर आ गया। ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से गिरावट हुई। ▶▶पेज 13

कार ने बाइक को मारी टक्कर, मौत

शाहदरा के कृष्णा नगर में सोमवार तड़के एक कार ने बुलट को टक्कर मार दी। शाहबाज (22) की मौत हो गई, जबकि दोस्त समीर (21) जख्मी हो गया। कार डिवाइडर पर चढ़कर मेट्रो पिलर से टकरा गई। कार में मौजूद युवक भाग गया।

बाल गिरने से रोकने की दवा का ट्रायल

पुरुषों में गिरते सिर के बालों को रोकने के लिए दवाई बनाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड की कॉस्मो फार्मास्यूटिकल्स ने क्लासकोटेरोन (Clascoterone) नाम की दवा बनाने की बात कही है। 31 नवंबर को दवा के ट्रायल के नतीजे घोषित कर उन्हें बेहतर बताया गया है।

जागरूक जनता jagrukjanta.net फेसबुक पेज
पढ़े, जुड़े और आगे बढ़े
हर खबर से आपको रखें अपडेट जागरूक जनता
www.facebook.com/jagrukjantanews

सरकार ने कहा, इंडिगो पर ऐसा ऐक्शन लेंगे जो मिसाल बनेगा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

नई दिल्ली: इंडिगो पर राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, सरकार ने उड़ानें रद्द किए जाने की जांच शुरू कर दी है। हम जांच कर रहे हैं। हम न सिर्फ इस मामले में, बल्कि एक मिसाल पेश करने के लिए भी एयरलाइन के खिलाफ बहुत, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। नायडू ने स्पष्ट किया कि इंडिगो संकट ऑटोमैटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) से नहीं, बल्कि इंडिगो के अंदरूनी क्रू रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ी और गलत मैनेजमेंट से हुआ।

बुधवार को तलब किए जा सकते हैं इंडिगो के सीईओ

वहीं, CEO और COO ने एविएशन रेगुलेटर DGCA के नोटिस का जवाब दे दिया है। एक दिन की मोहलत के बाद भी इंडिगो ने जवाब में उड़ानें डिले होने का ठोस कारण नहीं बताया है। DGCA ने कहा कि जवाब देते हुए इंडिगो ने माफी मांगी है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय और DGCA में लगातार चल रही मीटिंग के बाद लगभग तय है कि इंडिगो से लेकर DGCA में कई टॉप अफसरों पर गाज गिरने वाली है। (एजेंसी इनपुट)

PTI

9,000 में से 4,500 लगेज वापस कर दिए गए हैं, बाकी अगले 36 घंटे में होंगे। ये जानकारी मंत्रालय ने दी।

DGCA का पैनल बुधवार को इंडिगो के CEO और COO को बुला सकता है। जांच के लिए ये 4 सदस्यीय पैनल 5 दिसंबर को बनाया गया था।

SC नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस से संबंधित याचिका को अर्जेंट सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले से मामले में संज्ञान ले चुकी है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए लगा दिया, जिसमें इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को मदद और टिकट के पैसे वापस दिलाने अनुरोध किया गया है।

500 फ्लाइट फिर रद्द, लगेज के लिए यात्री हुए परेशान

इंडिगो की सोमवार को भी करीब 500 फ्लाइट कैंसल हो गईं। सातवें दिन भी दिल्ली के टर्मिनलों पर अफरातफरी रही। टी-1 पर यात्रियों के लगेज भरे हुए विडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं, इंडिगो ने अपने जवाब में मंत्रालय को यह भी बताया कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर की आधी रात तक 9,55,591 यात्रियों के टिकट कैंसल हुए थे। जिनका 827 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया। इनमें से 5,86,705 यात्रियों के टिकट 1 से 7 दिसंबर के बीच हुए थे। जिनका रिफंड 569 करोड़ रुपये से अधिक था। एयरलाइंस ने बताया कि उसने यात्रियों के फंसे नौ हजार लगेज में से साढ़े चार हजार लगेज यात्रियों तक पहुंचा दिए हैं। बाकी अगले 36 घंटों में पहुंचाने का टारगेट है। ▶▶पेज 10

9,55,591 यात्रियों के टिकट कैंसल हुए

90 साल के प्रेम चोपड़ा के बिना ओपन हार्ट सर्जरी के बदले गए खराब वाल्व

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

मुम्बई। बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता प्रेम चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। बीते महीने अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। नवंबर में उन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिनों के इलाज और निगरानी के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था। अब उनकी तबीयत स्थिर है और वे घर पर आराम कर रहे हैं। इस बीच उनके दामाद और अभिनेता शरमन जोशी ने एक पोस्ट के जरिए फैंस को उनकी सेहत का

अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या हुआ था और उसका इलाज कैसे किया गया। शरमन ने अपने इंस्टाग्राम पर चोपड़ा की अस्पताल के दिनों की कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें डॉक्टर्स के साथ-साथ अभिनेता जितेंद्र भी नजर आ रहे हैं, जो उस समय उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे।

मेट्रो से घर तक का सफर होगा और स्मार्ट

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

दिल्ली मेट्रो अब अपने स्टेशनों से चलने वाले लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाहनों को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए डीएमआरसी ने आईआईटी हैदराबाद के TiHAN इनोवेशन हब के साथ समझौता किया है। इस तकनीक वाली गाड़ियों में स्वचालित नेविगेशन लगेगा, जो रास्ते में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या वाहन को देखकर खुद अपना मार्ग बदल सकेगी। पहले चरण में इसे मेट्रो डिपो और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ट्रायल के तौर पर लगाया जाएगा। सफल होने पर इसे स्टेशनों से चलने वाले वाहनों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। इस तकनीक से स्मार्ट, सुरक्षित मोबिलिटी का रास्ता खुलेगा।

File

आखिर क्या है स्वचालित नेविगेशन

IIT हैदराबाद के इनोवेशन हब ने इस तकनीकी पर एक गोल्फकार्ट तैयार किया है। यह बिना चालक के पूरे कैंपस में चलती है। इसकी खास बात यह है कि यह रास्ते में पड़ने वाले आबजेक्ट, ट्रैफिक व भीड़ के अनुसार अपना रास्त खुद बदल लेती है। अपना रफ्तार बढ़ाती और घटा भी सकती है।

15 से 18 तक दौरा

जॉर्डन, इथोपिया और ओमान जाएंगे PM मोदी

जागरूक जनता @नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन (15-16 दिसंबर), इथियोपिया (16-17 दिसंबर) और ओमान (17-18 दिसंबर) का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों का समर्थन करना और आर्थिक, व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करना है। जॉर्डन में पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला II के साथ व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, जबकि ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश सहयोग प्रमुख अजेंडे में रहेंगे। यह पीएम की ओमान की दूसरी और जॉर्डन की पहली यात्रा होगी।

आर्थिक, व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने पर फोकस

दिल्ली की CM ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका

PTI

- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संग अमृतसर पहुंचकर हरमंदिर साहिब में शीश नवाकर गुरु साहिब का शुकराना अदा किया।
- सीएम ने स्वर्ण मंदिर परिसर में बर्तन भी साफ किए। उन्होंने कहा कि लाल किला प्रांगण में आयोजित 'गुरमत समागम' सफल रहा।

सरकार ने चेताया, चीन यात्रा करते हुए अलर्ट रहें

जागरूक जनता @नई दिल्ली: भारत सरकार ने शंघाई हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिक के साथ हुई घटना पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है चीनी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय यात्रियों को मनमाने ढंग से रोका या परेशान नहीं किया जाएगा। चीन अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियमों का पालन करेगा। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा और ट्रांजिट के दौरान सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश के मामले पर जायसवाल ने कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

संपादक : ज्ञानेन्द्र मिश्रा मो.-9829329070, फोन : 0141-3587886, ईमेल : jagrukjantanews@gmail.com (सभी मामलों का न्याय क्षेत्र जयपुर) * पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के जिम्मेदार। संपादकीय कार्यालय : 132, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर-4, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302039 समाचार संपादक- चेतेन्द्र कुमार मिश्रा

खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठकः अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा

राजस्थान को खनन में अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता-शर्मा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। साथ ही, यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक नवाचार एवं एआई का उपयोग करते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके।

नीलामी प्रक्रिया में लाएं पूर्ण पारदर्शिता-

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि रोजगार को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा पुलिस, परिवहन एवं खान विभाग आपसी समन्वय कर अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन निर्धारण के लिए क्षेत्र में ड्रोन सर्वे को बढ़ाया जाए। साथ ही, खनन पट्टा क्षेत्रों एवं अवैध खनन स्थलों की जियो फैन्सिग को और प्रभावी बनाया जाए।

एम-सेण्ड को दिया जा रहा प्रोत्साहन

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एम-सेण्ड नीति 2024 जारी की गई है। इस नीति के माध्यम से एम सैंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे एम-सेण्ड के लिए प्रदेश में अनेक प्लांट्स संचालित हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी प्लांट्स की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में खनिज संसाधनों की संभावनाओं को जानने के लिए भी प्रभावी कार्ययोजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि खान विभाग द्वारा एम-सेण्ड पॉलिसी, मिनरल डवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अवैध माइनिंग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन, ई-रवन्ना, ई-टीपी के गलत इस्तेमाल के लिए टीम का गठन तथा अवैध खनन संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर होम गार्ड की तैनाती जैसे कार्य किए गए हैं। साथ ही, प्रदेश में खनन से रॉयल्टी वृद्धि हेतु खनिज परिवहन के लिए जीपीएस एवं आरएफआईडी युक्त वाहनों की बाध्यता की जा रही है। समस्त विभागीय एमपैनल्ड वे-ब्रिज पर स्टेण्डर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग, तुलायंत्रो पर सैंसर्स, ए.आई. कैमरा सहित विभिन्न नवाचार किए गए हैं।

इससे पहले प्रमुख शासन सचिव खान टी. रविकांत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के नवाचारों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रवासी राजस्थानी दिवस का आज जेईसीसी में होगा आयोजन

एक मंच पर होंगे देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी

एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग, विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को किया जाएगा सम्मानित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित किए जा रहे 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' कार्यक्रम में देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। 8,700 से अधिक लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। 10 दिसम्बर को जेईसीसी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। साथ ही, प्रवासी राजस्थानी नीति के साथ ही निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी नीतियों का अनावरण भी किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। साथ ही, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सहित कई उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रवासियों का सम्मान, सेक्टोरल सेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

इस एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ होगी। इसके बाद प्रवासी राजस्थानी संवाद और उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित सेक्टोरल सेशन होंगे। इन विशेष सत्रों में विविध विषयों पर होने वाले सेक्टोरल सत्रों में विशेषज्ञ राजस्थान के बदलते औद्योगिक एवं निवेश परिवेश और जुड़ाव की संभावनाओं पर विचार इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखेगी।

26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे

कार्यक्रम में सभी 26 राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें 12 अंतरराष्ट्रीय चैप्टर हैं, जिसमें म्यूनिख (जर्मनी), नैरोबी (केन्या), दुबई (यूएई), सिंगापुर (सिंगापुर), दोहा (कतर), टोक्यो (जापान), रियाद (सऊदी अरब), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), कंपाला (युगांडा), काठमांडू (नेपाल), लंदन (यूके), न्यूयॉर्क (यूएसए) शामिल हैं। साथ ही, 14 चैप्टर घरेलू हैं, जिसमें दिल्ली, रांची, गुवाहाटी, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और कोयम्बटूर शामिल हैं।

लगातर धरातल पर उतरता निवेश, 10 से अधिक नई नीतियां लॉन्च होंगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान में कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए थे, उनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। 10 दिसम्बर को एक लाख रुपये निवेश समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

विकास यात्रा का प्रगति पथ

कार्यक्रम स्थल पर प्रवासियों और उद्योगपतियों को राजस्थान के विकास से अवगत कराने के लिए प्रगति पथ थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पैनल और वीडियो फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से अवगत कराना है ताकि वे 'बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान' भाव के साथ अच्छी यादें लेकर लौटें।

प्रवासियों से संवाद-सहयोग के लिए अहम निर्णय

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इनमें सभी प्रवासियों को एक मंच पर लाने के लिए राजस्थानी दिवस की घोषणा, उनके हितों की रक्षा के लिए नए विभाग का गठन, नई प्रवासी राजस्थानी नीति जैसे निर्णय शामिल हैं। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारजन के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल प्वॉइंट कॉन्टेक्ट बनाया गया है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस

मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में 10 दिसम्बर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस कड़ी में पहला प्रवासी दिवस आयोजित किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी डायस्पोरा को साथ लाना और प्रवासियों को जोड़ना है।

विद्यार्थियों को दी तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

दौसा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) दौसा जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ दौसा व विकल्प इंडिया सोसाइटी, जयपुर के सहयोग से "तंबाकू-मुक्त विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम" का शानदार आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत चलाए गए इस पहल में दौसा जिले के सभी ब्लॉक के स्कूल-कॉलेजों में वाद विवाद ,चित्रकला, पोस्टर प्रदर्शनी और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित हुए।

विकल्प इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष संजय कटारा ने बताया कि ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से परिचित कराना और उन्हें रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सोसाइटी प्रतिनिधि हर विद्यालय महाविद्यालय में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, जिससे "तंबाकू-मुक्त विद्यालय" की नीति को धरातल पर उतारा जा सके। वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रों ने तंबाकू के सामाजिक और स्वास्थ्य-परिणामों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बाद आयोजित संवाद सत्र में शिक्षक, सोसाइटी के सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र-छात्राओं ने खुलकर प्रश्न पूछे और समाधान साझा किए। इस दौरान सभी स्कूलों के शिक्षक व विद्यार्थियों ने "तंबाकू-मुक्त" शपथ भी ली, जिससे भविष्य में इस दिशा में निरंतर प्रयास सुनिश्चित हो सके। विकल्प इंडिया सोसाइटी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव मिश्रा ने कहा, "हमारा लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाना है। जब बच्चे खुद ही तंबाकू से दूर रहने का संकल्प लेंगे, तभी हम एक स्वस्थ समाज की ओर कदम बढ़ा पाएँगे।"

यह जागरूकता अभियान NTCP के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें स्कूल-प्रोग्राम, IEC गतिविधियाँ और स्थानीय स्तर पर तंबाकू-नियंत्रण कानूनों की निगरानी शामिल है। दौसा जिले के सभी ब्लॉक में इस प्रकार के कार्यक्रमों का विस्तार जारी रहेगा, जिससे जिले को तंबाकू-मुक्त भविष्य की ओर ले जाया जा सके।

निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज समय उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध-डॉ. किरोडी

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राज्य के कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड समय पर मिले एवं इनकी कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष 2024-25 में रबी की बुवाई 95 लाख 85 हजार हैक्टेयर में की गई थी। रबी 2025-26 में 105 लाख 60 हजार हैक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी फसल का रकबा बढ़ा है। कृषकों को रबी 2025-26 में उच्च गुणत्ता के कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में रबी गुण नियंत्रण अभियान 23 सितम्बर से 15 नवम्बर तक चलाया गया। इस अभियान के तहत कृषि आदानों के कुल 304 निर्माताओं व विक्रेता परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 4 हजार 87 नमूने लेकर विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं में भिजवाये गये हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम की धाराओं का उल्लघंन करने पर 56 निर्माता, विक्रेता परिसर के लाइसेंस निलंबित तथा 8 फर्मो के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया डाइवर्जन को रोकने हेतु 24 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ताकि पात्र किसानों को समय पर यूरिया मिल सके। उक्त अभियान के तहत यूरिया डाइवर्जन के 420 कट्टे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कृषि आयुक्तालय स्तर से भी टीमों का गठन किया गया है जो कि जिलों में औचक निरीक्षण करने की कार्यवाही कर रहे हैं। सभी जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों को सघन निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है एवं इस प्रकार की ठोस कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी।

शकूरबस्ती-जैसलमेर-शकूरबस्ती रेलसेवा में बढाये विभिन्न श्रेणी के डिब्बे

जयपुर @ जागरूक जनता। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु शकूरबस्ती -जैसलमेर-शकूरबस्ती रेलसेवा में 01 थर्ड एसी व 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बो की अस्थाई बढोतरी की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 12249/12250, शकूरबस्ती-जैसलमेर-शकूरबस्ती रेलसेवा में शकूरबस्ती से दिनांक 09.12.25 से 16.12.25 तक एवं जैसलमेर से दिनांक 10.12.25 से 17.12.25 तक 01 थर्ड एसी व 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बो की अस्थाई बढोतरी की जा रही है।

आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय बैठक

निरोगी रहना मानव जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य- उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि निरोगी रहना मानव जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए अनेक अनमोल औषधियों एवं प्राकृतिक उपचार विधियों का वरदान दिया है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और जीवनशैली को आमजन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। डॉ. बैरवा मंगलवार को शासन सचिवालय में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निरोगी रहने, रोगों की रोकथाम करने और प्रकृति आधारित उपचार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक प्राकृतिक और संतुलित जीवनशैली अपनाकर स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी सके।

आयुष्मान गांवों को 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन

आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के पहले चरण में प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया हैं। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर वाली ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा। इन पंचायतों में 18 स्वास्थ्य सूचकांकों पर काम किया जायेगा और इन सूचकांकों की पूर्ण पालना वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

आरोग्य सखी से होगा गाँव-गाँव आयुष्मान

ग्राम पंचायतों में आरोग्य मित्र एवं आरोग्य सखियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। वे वरिष्ठ नागरिकों, बालिकाओं, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को वनौषधि परिचय, घरेलु उपचार, आहार-विहार, योग व्यायाम, बीपी व ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, नशामुक्ति जैसे सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों का ध्यान रखेगे।

जागरूक जनता
www.jagrukjanta.net
विश्वसनीय समाचार पत्र
जी हाँ,यदि आपको अपने प्रतिष्ठान का व्यापार का विज्ञापन देना है तो जागरूक जनता समाचार पत्र द्वारा पूरे राजस्थान के साथ-साथ 4 अन्य राज्यों में आपका विज्ञापन प्रसारित किया जायेगा।
जो दिखेगा वही बिकेगा
आज ही बुक करें विज्ञापन

आपके व्यापार की तरक्की जागरूक जनता के साथ
विज्ञापन क्लासीफाइड डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैवाहिक
विज्ञापन बुक करें : 9928022718 9829329070

दीया कुमारी की प्रधानमंत्री से मुलाकात

जयपुर @ जागरूक जनता। उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान संसद भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी मार्गदर्शन, सकारात्मक दृष्टि और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी सादगी, जनसेवा का जुनून और नेतृत्व क्षमता मानव कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

कोटा-बूंदी समेत 4 जिलों के करीब 3 लाख परिवार को सीधा फायदा

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले के लाखों लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीने के शुद्ध पानी से जुड़ी दो बड़ी परियोजना को मुख्यमंत्री भजनलाल ने मंजूरी दे दी है। दोनों योजनाओं के पूरा होने के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले के लाखों परिवारों को नल से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल जीवन मिशन के तहत जारी इन परियोजनाओं पर कुल 5184 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

परियोजना पर आएगा 3523 करोड़ का खर्चा

परवन अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़, बारां और कोटा जिले के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके तहत बारां के 907 गांव, कोटा के सांगोद क्षेत्र के 184 गांव और झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1402 गांव और 276 ढाणियों तक शुद्ध पानी पहुंचेगा। इन जिलों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। परवन अकावद पेयजल परियोजना पर 3523 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत कोटा और झालावाड़ में दो इन्टैक पंप गृह, दो जल शोधन संयंत्र, 41 स्वच्छ जलाशय और 276 उच्च जलाशयों का निर्माण होगा। बारां, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में कुल 661 किलोमीटर लंबी मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। परवन अकावद परियोजना में कुल 9477 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन और वितरण पाइप लाइन तैयार की जाएगी।

1661 करोड़ की है नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना

जानकारी के मुताबिक, कोटा और बूंदी के 749 गांव और छह कस्बों के 01 लाख 13 हजार 287 परिवारों को नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना से हर घर जल मिलेगा। इस परियोजना की लागत 1661 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके तहत कोटा और बूंदी क्षेत्र में एक इन्टैक पंप गृह निर्माण, तीन जल शोधन संयंत्र, 14 स्वच्छ जलाशय और 137 उच्च जलाशयों का निर्माण होगा। परियोजना के लिए 58.45 किलोमीटर लंबी रॉ वॉटर राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नौनेरा परियोजना के तहत 4506 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण और ग्रामीण वितरण पाइप लाइन भी तैयार होगी। दोनों जिलों में चौदह पंप गृह बनाए जाएंगे।

आरएएस भर्ती-2023: 78 अभ्यर्थियों को 11 दिसंबर तक वांछित दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से करने होंगे प्रस्तुत

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा-2023 के साक्षात्कार दौरान वांछित दस्तावेजों के अभाव में प्रोविजनल रखे गए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने का अंतिम अवसर दिया है। आयोग ने ऐसे 78 अभ्यर्थियों की सूची वांछित दस्तावेज एवं कारण सहित अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। आयोग सचिव ने बताया कि इन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के दौरान दस्तावेजों की कमी के कारण प्रोविजनल रखा गया था। इन्हें साक्षात्कार के समय भी दस्तावेज जमा कराने के लिए पत्र दिया गया था और उसके बाद स्मरण पत्र जारी करते हुए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक वांछित दस्तावेज पूरे नहीं किए गए हैं। सूचीबद्ध प्रोविजनल अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार अपने वांछित दस्तावेज मूल रूप में, स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग कार्यालय में 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करवाने होंगे। वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द करते हुए चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बॉलीवुड-स्टाइल शादी

अनुयायियों की भावना बनाम आधुनिकता का आवरण

नविता
समाजविद्
@jagrukjanta.net

5 दिसंबर को जयपुर के ताज आमेर होटल में हुई कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। वैदिक रीति के साथ बॉलीवुड ग्लैमर का मेल देखकर उनके लाखों अनुयायी असमंजस में पड़ गए। क्या धर्म प्रचारक, कथा वाचक और संतो को इस तरह के 'शादी-स्पेशल' आयोजन में शामिल होना चाहिए? इस लेख में हम दोनों पक्षों की तर्कों का विश्लेषण करेंगे। कथावाचक इंद्रेश जी का नाम आध्यात्मिक जगत में प्रभाव रखता है और लोकप्रिय हैं। उनकी शादी में शेरवानी, घुड़चढ़ी, हल्दी-मेहंदी, संगीत और बीप्राक जैसे गायकों की मौजूदगी ने फिल्मी माहौल बना दिया। अनुयायियों की संख्या लाखों में है, जो उनके हर कदम को ध्यान से देखते हैं।

समर्थकों का तर्क

आधुनिकता का स्वीकार

» समय के साथ चलना और युवाओं को आकर्षित करना।
» शादी व्यक्तिगत पर्व है, जिसमें खुशी मनाने के तरीके बदल सकते हैं।
» **सकारात्मक प्रचार**-कुछ लोग इसे धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में देख रहे हैं।
» बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति से धर्म का सकारात्मक प्रचार।
» सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से नए लोगों तक संदेश पहुंचा।
» **संस्कृति का मिश्रण** - वैदिक मंत्रों के साथ आधुनिक संगीत का मिश्रण, 'संस्कृति और समकालीनता' का अनोखा प्रयोग।

विरोधियों का तर्क

1. संत की मर्यादा

» संतों से समाज को वैराग्य और सरलता की उम्मीद होती है।
» भव्यता और ग्लैमर अनुयायियों को गलत संदेश दे सकता है।

2. धर्म की विपरीत दिशा

» शास्त्रों में संतों के लिए विवाह को 'निमित्त मात्र' बताया गया है।
» अत्यधिक ऐश्वर्य प्रदर्शन धर्म के मूल्यों के विरुद्ध।
» **परंपरा बनाम प्रगतिः** संत समाज अक्सर परंपरा के पालन को प्राथमिकता देता है। लेकिन आज का युवा वर्ग डिजिटल माध्यमों से जुड़ा है, जहाँ आकर्षक आयोजन ज्यादा वायरल होते हैं।
» **दृष्टांत की भूमिकाः** संतों को आदर्श माना जाता है। उनके जीवन का हर पहलू अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है।
» **संतुलन की जरूरतः** यदि आधुनिकता को अपनाना ही है, तो उसे धार्मिक मर्यादाओं के साथ संतुलित रखना ज़रूरी है।

इंद्रेश जी की शादी ने एक बहस छेड़ दी है – लाखों अनुयायियों वाले आध्यात्मिक कथा वाचकों को क्या व्यक्तिगत खुशियों के लिए आधुनिक ग्लैमर अपनाना चाहिए? दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। यदि यह आयोजन उनके अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करता और धर्म की मूल भावना को नहीं छेड़ता, तो शायद यह स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन अगर इससे आस्था पर आंच आती है, तो आध्यात्मिक परिवेश वाले कथा वाचकों को अपने आचार-विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए।

» क्या आपको लगता है कि कथा वाचक इन्द्रेश जी की शादी जैसी व्यवस्था (निजी जिंदगी) को भी सार्वजनिक रूप से इतना ग्लैमरस होना चाहिए?

शास्त्रों में आध्यात्मिक गुरुओं के अलावा संतों के विवाह का वर्णन मिलता है। विशेषतः इनमें आचार संहिता होनी चाहिए?

(यह लेख तटस्थ विश्लेषण है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं। ये लेखक के अपने विचार है)

साहित्य में नाम कर रही झाझड की बहू

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

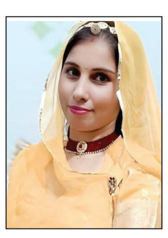

कहते हैं कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है शेखावाटी के झाझड गाँव की बहू सुमन राठौड़ ने। हनुमानगढ़ की बेटी सुमन की कम उम्र में ही वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद एम ए ,बी एड तक की पढ़ाई ससुराल में गृहस्थ जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूर्ण की। साहित्य में रुचि रखने वाली सुमन अपनी कलम की ताकत से अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्यिक संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी है।गद्य एवं काव्य दोनों विधाओं में उत्कृष्ट पकड़ रखने वाली सुमन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की प्रतिभागी बन विजेता सूची में रह अनेकों अवार्ड अपने नाम कर झाझड, शेखावाटी का नाम रोशन कर चुकी है। देश की 20 से अधिक साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में उनकी 80 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। गौरतलब है की झाझड गांव की यह बहू राइटर ही नहीं अपितु ओजस्वी वक्ता के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी है। महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं।

कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024: आयोग ने जारी की मॉडल उत्तरकुंजियां, अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। आरपीएससी ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान तथा प्रश्न पत्र द्वितीय-सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी की हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर तक किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 10 से 12 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है। ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें।

नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशल और समन्वय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिये 'कौशलम्' प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में प्रशासनिक कार्यों एवं गतिविधियों की बेहतर समझ, समन्वय तथा कुशल संचालन हेतु क्षमता निर्माण के अंतर्गत कुलपती प्रो. संजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 'कौशलम्' का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के सभी विभागो के विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा "कौशलम् 2025 संस्थान में सहयोग, समन्वय और टीम-आधारित कार्य संस्कृति को मजबूत करेगा।

कौशलम् 2025 में टीम की शक्तियों एवं कमजोरियों की पहचान, प्रभावी टीमवर्क रणनीतियों का निर्माण तथा यह समझना था कि नेतृत्व के व्यवहार का संस्थागत प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चर्चा में यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि अलग-थलग कार्य करने की प्रवृत्ति से हटकर अंतर-विभागीय सहयोग, समन्वय एवं साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित की जाए। प्रशिक्षण के दौरान अनेक सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें संवादात्मक केस स्टडीज़, प्रतिभागी-नेतृत्व वाले व्याख्यान और व्यावहारिक प्रबंधन अभ्यास शामिल थे। प्रत्येक प्रतिभागी को संस्थागत प्रशासन, शैक्षणिक तंत्र, चिकित्सालय प्रबंधन, अनुसंधान प्रक्रियाओं तथा रोगी सेवा से संबंधित एक वास्तविक परियोजना दी गई। टीमों ने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए तथा पक्षङ्कविपक्ष के तर्क-वितर्क में भाग लिया। इससे प्रतिभागियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान तथा सहयोगात्मक निर्णय लेने की क्षमता का सशक्त विकास हुआ।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को नेतृत्व व्यवहार, टीमवर्क, प्रबंधन रणनीतियों और विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी गई। संवादात्मक केस स्टडीज़ व चर्चा सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण किया। प्रत्येक समूह को प्रशासन, शैक्षणिक ढांचे, चिकित्सालय प्रबंधन, अनुसंधान प्रक्रियाओं तथा रोगी सेवा से जुड़ी वास्तविक परियोजनाएँ सौंपी गईं। प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रतिभागियों ने पक्ष-विपक्ष में तर्क रखे और समस्या समाधान पर अपने विचार साझा किए। करीब 10 घंटे चले इस प्रशिक्षण में समूह गतिविधियाँ, रोचक खेल और संगीत सत्र ने प्रतिभागियों में नई ऊर्जा और सौहार्द भरा।

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष: 810 नई बसें और 352 अनुबंधित बसों ने बदली रोडवेज़ की तस्वीर

सरकार के सुशासन, दूरदर्शिता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का परिचायक है रोडवेज

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। परिवहन व्यवस्था किसी भी प्रदेश के आधारभूत ढांचे की आत्मा होती है जो वहाँ की प्रगति और जनजीवन की सुगमता का आधार होती है। यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का माध्यम भर नहीं है बल्कि आर्थिक गतिविधियों की रीढ़, सामाजिक जुड़ाव का आधार और आमजन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सबसे भरोसेमंद तंत्र होती है।

विशेषकर राजस्थान जैसे विशाल भूगोल वाले राज्य में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत से अधिक लोग निवास करते हैं, वहाँ ऐसी विश्वसनीय और किफायती परिवहन सेवा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों से लेकर नौकरीपेशा युवा, किसान, व्यापारी तथा सामान्य यात्री तक सभी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा रोडवेज़ की सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

पुनरुत्थान का नया अध्याय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि यदि रोडवेज़ को पूरी तरह आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है तो इसके बेड़े का नवीनीकरण अनिवार्य है। यही कारण है कि वर्तमान सरकार के गठन के साथ ही लंबे समय से लगातार घाटे, पुरानी होती बसों और कम होती यात्रियों की संख्या जैसी चुनौतियों का सामना कर रही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के रिवाइवल का कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को किफायती और सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सुपरविजन को मजबूत किया गया। वर्षों से रोडवेज़ के घाटे का बड़ा कारण रही डीजल की छीजत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके साथ ही रूट प्लानिंग, बस संचालन और संसाधनों के उपयोग को व्यवस्थित करते हुए यात्रियों की संख्या और बसों द्वारा प्रतिदिन तय किए जाने वाले औसत किलोमीटर में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। इन तमाम सुधारों ने रोडवेज़ के दैनिक संचालन को नई ऊर्जा और स्थिरता प्रदान की जिसने रोडवेज की वर्तमान नवीन तस्वीर सामने आई। इन समेकित प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम यह सामने आया कि संचालन घाटा, जो पहले लगभग एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था, वह घटकर करीब तीन सौ करोड़ रुपये रह गया है। यह कमी राजस्थान रोडवेज़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में गिनी जा रही है और इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों, सरि य नेतृत्व और सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है।

810 नई बसें और 352 अनुबंधित बसें जिन्होंने बदली रोडवेज़ की तस्वीर

यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए 810 नई बसों को खरीदा गया और 352 बसों को अनुबंध के आधार पर शामिल किया गया। नई बसों के जुड़ने से जहां जनता को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा मिलने लगी, वहीं बढ़े हुए नेटवर्क और बेहतर सेवाओं ने रोडवेज़ की कमाई पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। राज्य सरकार के द्वारा निरंतर लिए जा रहे लोककल्याणकारी निर्णय इस बात का परिचायक है कि लेकिन यह परिवर्तन केवल शुरुआत है। आने वाले समय में रोडवेज़ के बेड़े में 800 और नई बसें शामिल की जानी हैं। इससे न केवल प्रदेश के अधिक क्षेत्रों में बेहतर बस सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि रोडवेज़ के तेजी से कम हो रहे घाटे को पूरी तरह समाप्त कर उसे लाभदायक इकाई बनाने का लक्ष्य भी पूरा होगा।

इंडिगो संकट ने खोली भारत के विमानन ढांचे की परतें

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

राम शर्मा
पत्रकार
@jagrukjanta.net

भारत का सिविल एविएशन क्षेत्र पिछले दो दशकों में जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसने देश को विश्व के सबसे व्यस्त विमानन बाजारों में शामिल कर दिया है। हवाई यात्रा अब किसी विशिष्ट वर्ग तक सीमित विलासिता नहीं रही, बल्कि सामान्य भारतीय यात्रियों की दिनचर्या में शामिल होती जा रही है। घरेलू उड़ानों की उपलब्धता, कम किराए वाली एयरलाइनों का बढ़ता नेटवर्क, और छोटे शहरों में भी हवाई अड्डों का विकास इस परिवर्तन की मुख्य वजहें हैं। सरकार की योजनाओं और निजी क्षेत्र की सक्रियता ने मिलकर भारतीय आसमान को और विस्तृत बनाया है, जहाँ प्रतिदिन लाखों यात्री उड़ान भरते हैं।

इस तेज़ विकास के बावजूद, भारतीय विमानन क्षेत्र कई जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में उत्पन्न अव्यवस्था ने इन चुनौतियों को एक बार फिर उजागर किया है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में इंडिगो का परिचालन अचानक चरमरा गया, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। क्रू-आराम नियमों में किए गए नए संशोधनों के चलते एयरलाइन को अपने रोस्टर में तत्काल बदलाव करने पड़े। न्यू नियमों में पायलटों और क्रू को अधिक आराम अवधि देने, रात के उड़ान घंटों को सीमित रखने और साप्ताहिक अवकाश को आराम अवधि में शामिल न करने जैसी व्यवस्थाएँ लागू की गईं। उद्देश्य उड़ान सुरक्षा को मजबूत बनाना था, किंतु इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए एयरलाइन को पर्याप्त संक्रमण अवधि नहीं मिल पाई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर देरी, रद्द उड़ानें और क्रू की कमी की स्थिति पैदा हो गई।

इंडिगो के पास घरेलू हवाई बाजार का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए उसकी किसी भी परेशानी का असर पूरे विमानन ढांचे पर पड़ना स्वाभाविक था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री घंटों फँसे रहे। कई उड़ानें आधी रात तक रोक दी गईं, और एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर शिकायतों और नाराजगी की बाढ़ आ गई। समयपालन क्षमता गिरकर 20 प्रतिशत के नीचे पहुँच गई, जो किसी भी बड़ी एयरलाइन के लिए अभूतपूर्व स्थिति मानी जाती है। एयरलाइन के कर्मचारियों को भी अचानक बढ़े दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि यात्रियों की संख्या और असंतोष दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपात बैठकें आयोजित की गईं और एयरलाइन को विस्तृत परिचालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। कुछ नियमों में अस्थायी छूट देकर उड़ानों को क्रमशः सामान्य करने की कोशिश की गई। सरकार ने एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की, जो यह पता लगाएगी कि क्या एयरलाइन ने नियामकीय बदलावों के प्रति आवश्यक तैयारी की थी या फिर प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेने में चूक हुई। यात्रियों को रिफंड और पुनर्बुकिंग की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। एयरलाइन ने दावा किया कि कुछ ही दिनों में उसका परिचालन लगभग 95 प्रतिशत तक सामान्य हो गया है, लेकिन यात्रियों का भरोसा लौटने में समय लगना स्वाभाविक है। इस अव्यवस्था ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या भारत का विमानन ढांचा अचानक आने वाले दबाव को संभालने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। एविएशन क्षेत्र की तेज़ वृद्धि के साथ एयरलाइंस और नियामकीय संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है, परंतु उन्हें लागू करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि यात्रियों पर अनावश्यक भार न पड़े और एयरलाइंस को समुचित तैयारी का समय मिल सके। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने रोस्टर, पायलट-उपलब्धता, और परिचालन योजनाओं को संभावित बदलावों को ध्यान में रखकर तैयार रखे, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण के दौरान यात्रियों की परेशानी न बढ़े।

यह मुद्दा इस तरफ भी संकेत करता है कि भारत का विमानन बाजार एक ही एयरलाइन पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। अगर 60 प्रतिशत घरेलू यातायात एक कंपनी पर आधारित हो, तो उसकी किसी भी गलती या संकट का सीधा असर पूरे सिस्टम पर पड़ना तय है। इससे न केवल यात्रियों की परेशानी बढ़ती है, बल्कि अन्य एयरलाइनों पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। विविधता और प्रतिस्पर्धा किसी भी उद्योग की मजबूती का आधार होती है, और विमानन क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। इसलिए अब यह जरूरत महसूस की जा रही है कि नई एयरलाइनों को प्रोत्साहित किया जाए तथा मौजूदा एयरलाइनों को अपनी परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक नीति समर्थन मिले।

विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का हवाई सफर भविष्य में और भी तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए ढाँचागत क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य है। बड़े एयरपोर्ट्स पहले ही अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हवाई अड्डों का विस्तार, रनवे क्षमता में वृद्धि, और ग्राउंड स्टाफ तथा सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता में सुधार आवश्यक है। इसके साथ ही एयरलाइंस को भी अपने मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना होगा। पायलटों और क्रू का प्रशिक्षण, समयपालन की संस्कृति, और सेवा-मानकों में सुधार हवाई यात्रा की विश्वसनीयता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इंडिगो की हालिया अव्यवस्था ने यह भी याद दिलाया कि विमानन क्षेत्र सिर्फ आर्थिक या तकनीकी प्रगति पर आगे नहीं बढ़ सकता; इसे प्रशासनिक परिपक्वता और दीर्घकालिक योजना की भी आवश्यकता है। यात्रियों का भरोसा इस उद्योग की रीढ़ है, और जब वह डगमगाता है तो पूरा ढाँचा हिल जाता है। इस घटना ने संकेत दिया है कि तेज़ विकास के साथ-साथ संतुलन, स्थिरता और तैयारी का होना भी उतना ही आवश्यक है।

कुल मिलाकर, भारत का सिविल एविएशन क्षेत्र आज महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक ओर यह देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, तो दूसरी ओर इंडिगो जैसी घटनाएँ यह बताती हैं कि विकास की गति को संभालने के लिए कई सुधार तुरंत लागू करने होंगे। बेहतर समन्वय, पारदर्शिता, और दूरदर्शी नीति-निर्माण के माध्यम से भारत अपने विमानन क्षेत्र को न सिर्फ संकटों से बचा सकता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर और भी अधिक मजबूत और विश्वसनीय बना सकता है।